मेट्रो Rays
आगे रखने का वादा
सांध्य दैनिक
रांची, गुरुवार, 10 सितंबर 2026
संवत 2083, भाद्रपद कृष्ण 13 मूल्य-2 रुपये
वर्ष-10, अंक 06 , पृष्ठ-8, RNI No.-JHAHIN/2017/75028

4 ▸▸ विफलता से ज्यादा खतरनाक है विफल महसूस करना
क्या केबीसी छोड़ेगें अमिताभ बोलें- शो को होस्ट करना मुश्किल है, बहुत दिल तोड़ने वाला अनुभव रहा है 6

दो माह में जेपीएससी अध्यक्ष और मेंबर नियुक्त करे सरकार : हाईकोर्ट

संवाददाता

रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को दो माह में जेपीएससी में अध्यक्ष और मेंबर की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। इससे पहले सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहित राय एवं विभोर मयंक ने कोर्ट बताया कि दो माह में जेपीएससी अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने की संभावना है। जिस पर कोर्ट ने 18 नवंबर तक सरकार को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 19 नवंबर निर्धारित की।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जेपीएससी में अध्यक्ष और मेंबर की नियुक्ति पूरी कर लेने की समय सीमा सरकार से मांगी थी। वन विभाग में अधिकारियों एवं कर्मियों की कमी से संबंधित कोर्ट के स्वत संज्ञान की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई।

हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। मामले में जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने कोर्ट को बताया गया कि अस्सिटेंट कंजरवेटर आफ फॉरेस्ट एवं रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की परीक्षा प्रक्रिया रद्द कर दी गई है।

हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश 6 माह में पूरी करे जेट परीक्षा

रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी को निर्देश दिया है कि राज्य सरकार की अधियाचना मिलने के बाद 6 माह में झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट (जेट) परीक्षा पूरी करें। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जेट 2024 परीक्षा, जिसे राज्य सरकार ने रद्द कर दिया है, उसके संदर्भ में अगर कोर्ट का कोई आदेश आता है तो उस आदेश से आज के हाईकोर्ट का आदेश प्रभावित होगा।

कोर्ट ने कहा कि जेईटी परीक्षा के बाद सरकार जल्द राज्य के विश्वविद्यालयो में एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करे। कहा कि विद्यालयों में प्रोफेसर के पदों को लंबी अवधि तक खाली रखना छात्रों के हित में उचित नहीं है।

इससे पहले सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जेट 2024 परीक्षा रद्द कर दिया गया है। राज्य के विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई हुई।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार एवं अधिवक्ता नितेश्वरी कुमारी ने पक्ष रखा।

इंटरनेट कनेक्शन काटे जाने पर हाइकोर्ट ने सरकार से किया सवाल

रांचीः शहर में केबल एवं इंटरनेट तारों के सही ढंग से नहीं लगे होने से संबंधित कोर्ट के स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बीते दिन झारखंड हाईकोर्ट का इंटरनेट कनेक्शन काटे जाने पर सरकार से सवाल किया। इस दौरान झारखंड बिजली वितरण निगम के सीएमडी अदालत में हाजिर हुए।

कोर्ट ने कहा कि पिछले दो सप्ताह से बिना सूचना के रांची शहर के विभिन्न इलाकों में पोल पर लगे इंटरनेट तारों को काट दिया जा रहा है। इससे शहर की इंटरनेट सेवा प्रभावित हो रही हैं। इंटरनेट सेवा काटे जाने से झारखंड हाईकोर्ट में भी काम प्रभावित हो रहा है। हाईकोर्ट के इंटरनेट सेवा को पुनर्बहाल (रिस्टोर) क्यों नहीं किया गया।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई आज दोपहर 2:15 बजे फिर रखी है, तब तक सरकार को हाईकोर्ट की इंटरनेट सेवा पुनर्बहाल करने का निर्देश दिया गया है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई,

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से पूछा था किन-किन टेलीकॉम कंपनी को केबल एवं इंटरनेट तार लगाने की परमिशन दी गई है और उनमें से कितना यूज किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा था कि इंटरनेट एवं केबल तार रांची शहर में अगर सही तरीके से नहीं लगे हुए हैं और नीचे की ओर तार झूले में है तो उसके लिए

झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जिम्मेवार है। कोर्ट ने उटऊ से यह भी पूछा है कि रांची में नीचे की ओर झूले केबल तार के लिए कौन अधिकारी जिम्मेवार है और उन पर क्या कार्रवाई हुई?

शराब घोटाला

जमानत मिलने के बाद आईएएस विनय चौबे निलंबन मुक्त, कार्मिक विभाग में दिया योगदान

मेट्रो रेज

रांची : झारखंड सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे का निलंबन रद्द कर दिया है। निलंबन मुक्त होने के तुरंत बाद उन्होंने कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में अपना योगदान दे दिया है। बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था।

शराब घोटाले में क्या हैं मुख्य आरोप? : विनय चौबे पर झारखंड की पूर्ववर्ती शराब नीति के दौरान बड़ा वित्तीय नुकसान पहुंचाने का आरोप है। एसीबी की जांच के अनुसार, उन्होंने मैनपावर सप्लाई करने वाली निजी एजेंसियों के साथ मिलकर एक आपराधिक

साजिश रची। इस सांठगांठ के जरिए सरकारी राजस्व को भारी चपत लगाई गई और निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इसी मामले में गहन पूछताछ के बाद एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

म्यूटेशन से जुड़े दो और मामले दर्जः जेल जाने के बाद विनय चौबे की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब उनके खिलाफ दो अन्य प्राथमिकी दर्ज की गईं।अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन का अवैध म्यूटेशन कराना। दूसरा मामला यह था कि अपने करीबियों और रिश्तेदारों के नाम पर नियमों को ताक पर रखकर कीमती जमीनों का म्यूटेशन स्वीकृत कराना।

अदालत से जमानत के बाद बहालीः इन सभी मामलों में अदालत से नियमित जमानत मिलने के बाद विनय चौबे जेल से बाहर आए। जेल से रिहा होने और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत निलंबन की अवधि समीक्षा के बाद, राज्य सरकार ने उनके निलंबन को समाप्त करने का आदेश जारी किया। फिलहाल कार्मिक विभाग में योगदान देने के बाद अब सरकार द्वारा उन्हें नई पदस्थापना (पोस्टिंग) सौंपी जानी बाकी है।

रांची रेलवे स्टेशन के पास लावारिस हालत में मिला नवजात, अस्पताल में भर्ती

रांचीः रांची रेलवे स्टेशन के पास स्थित रेलवे ऑफिसर्स कॉलोनी की गली में एक नवजात लावारिस हालत में मिला। यह गली सेरसा स्टेडियम के सामने स्थित है। रोने की आवाज सुनकर युवक की नजर कपड़े में लिपटे नवजात पर पड़ी और उसने तुरंत आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इसी दौरान एक युवक को गली के किनारे से रोने की आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखने पर पता चला कि कपड़े में एक नवजात लिपटा है। लोगों ने मामले की जानकारी आरपीएफ को दी। घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और नवजात को अपने संरक्षण में लेकर तत्काल अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों की निगरानी में बच्चे का इलाज चल रहा है। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

रांची जिला बल के 459 पुलिसकर्मियों का तबादला

रांचीः रांची जिलाबल के 400 से अधिक पुलिसकर्मियों और हवलदारों का तबादला कर दिया गया है। इसका आदेश रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक ने जारी कर दिया है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। सभी को आदेश दिया गया है कि अविलंब नव पदस्थापन पर योगदान दें। योगदान के बाद अनुपालन प्रतिवेदन देने को भी कहा गया है।

1993 मुंबई बम ब्लास्ट : अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, समय से पहले रिहाई की याचिका खारिज

मुंबई : 1993 मुंबई सीरियल बम धमाकों के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे गैंगस्टर अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उसकी समय से पहले रिहाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही फिलहाल जेल से बाहर आने की उसकी उम्मीदों को झटका लगा है।

यह मामला देश के सबसे भयावह आतंकी हमलों में शामिल है। 12 मार्च 1993 को मुंबई के 12 अलग-अलग इलाकों में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में 257 लोगों की मौत हुई थी, जबकि करीब 800 लोग घायल हुए थे। जांच में सामने आया था कि बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेने के मकसद से इन धमाकों की साजिश रची गई थी। अबू सलेम को इस साजिश में अहम भूमिका निभाने वाला आरोपी माना गया। जांच के दौरान यह सामने आया कि वह हमले की योजना में शामिल था और उसने गुजरात के भरुच से मुंबई तक हथियार और विस्फोटक पहुंचाए थे। उसे हत्या के मामले में भी दोषी ठहराया गया था।

इन मामलों में विशेष टाडा अदालत ने सलेम को 25 साल की कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद से वह जेल में सजा काट रहा है।

अबू सलेम इससे पहले भी अदालत में दलील दे चुका है कि पुर्तगाल के साथ हुए प्रत्यर्पण समझौते के तहत उसे 25 साल से अधिक समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। हालांकि, उसकी इस दलील को अदालतें कई बार खारिज कर चुकी हैं।

इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी सलेम की समय से पहले रिहाई से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि सजा में मिलने वाली छूट की गणना रिहाई की निर्धारित तारीख से सिर्फ एक महीने पहले की जा सकती है। ऐसे में अभी यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उसकी सजा पूरी हो चुकी है।

खूंटी में पेट्रोल पंप पर फायरिंग, पीएलएफआई के नाम पर मांगी 10 लाख रंगदारी

खूंटीः शहर के भगत सिंह चौक स्थित दास पेट्रोल पंप पर बुधवार की रात बाइक सवार दो अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग कर सनसनी फैला दी। वारदात के बाद कथित रूप से पीएलएफआई के नाम से जारी एक पर्चा मौके पर छोड़कर पेट्रोल पंप संचालक एवं ठेकेदार अमित साहू से दो दिनों के भीतर 10 लाख रुपये संगठन को सहयोग के रूप में देने की मांग की गई है। रकम नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई है।

घटना रात करीब साढ़े नौ बजे की बताई जा रही है। उस समय अमित साहू पेट्रोल पंप पर मौजूद नहीं थे। जानकारी के अनुसार,

बाइक से पहुंचे दो युवकों ने पेट्रोल पंप परिसर में एक गोली चलाई और पर्चा छोड़ने के बाद तोरपा रोड की ओर फरार हो गए। फायरिंग में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। गोली चलने के बाद पेट्रोल पंप पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही एसडीपीओ मंगल सिंह जमुदा और सदर थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह सशस्त्र बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा और कथित पीएलएफआई का पर्चा बरामद किया। पर्चा जोनल कमांडर राजेश यादव के नाम से जारी बताया जा रहा है। अमित साहू ने पुलिस को बताया कि उन्हें पूर्व में भी धमकियां मिल चुकी हैं और कुछ वर्ष पहले परवल स्थित उनके घर पर हमला भी हुआ था। पुलिस ने पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। फुटेज में दोनों युवक बाइक से पहुंचकर फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। चेहरे ढके होने के कारण पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी है।

सिमडेगा में नौकरी दिलाने के नाम पर 5-6 करोड़ की ठगी

सिमडेगाः नौकरी दिलाने के नाम पर सिक्योरिटी मनी वसूलकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले कथित संगठित गिरोह का पुलिस ने पदार्फाश किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना ओम प्रकाश समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक श्रीकांत एस। खोटरे ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रारंभिक जांच में करीब पांच से छह करोड़ रुपए की ठगी सामने आई है।

मामला बानो और कुरडेग थाना क्षेत्र से जुड़ा है। स्थानीय ग्रामीणों ने भिएसके फाउंडेशन संस्था पर नौकरी दिलाने के नाम पर रुपए लेकर ठगी करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर बानो थाना में कांड संख्या 27/26 और कुरडेग थाना में कांड संख्या 36/26 दर्ज कर जांच शुरू की गई।

एसआईटी ने तकनीकी और मानवीय सूचना से की कार्रवाईः मामले के उद्भेदन के लिए एसपी श्रीकांत एस खोटरे के निर्देश पर वरीय पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) रनवीर सिंह और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धर्मदेव पासवान के संयुक्त नेतृत्व में एसआइटी का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं।

ब्रिक्स समिट के लिए भारत आ सकते हैं शी जिनपिंग

7 साल बाद भारतीय जमीन पर पीएम मोदी से होगी मुलाकात

नई दिल्ली/बीजिंगः चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आ सकते हैं। बीजिंग में चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से गुरुवार को उनके भारत दौरे का आधिकारिक ऐलान किए जाने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति शी शनिवार दोपहर दिल्ली पहुंच सकते हैं। इसके बाद शाम करीब 6 बजे भारत मंडपम में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हो सकती है।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच भारत मंडपम में द्विपक्षीय बैठक भी प्रस्तावित है। दोनों नेताओं की यह मुलाकात भारत-चीन संबंधों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है।

खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की भारतीय जमीन पर करीब 7 साल बाद पहली द्विपक्षीय मुलाकात होगी। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़पों के बाद दोनों नेताओं की भारत में यह पहली द्विपक्षीय बैठक होगी। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर इस मुलाकात पर रहेगी। भारत 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है।

सम्मेलन में ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के नेता वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा राजनीतिक-सुरक्षा, आर्थिक-वित्तीय और लोगों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर भी विचार-विमर्श होगा। वर्ष 2026 में ब्रिक्स की स्थापना के 20 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं।

शी जिनपिंग की पिछली भारत यात्रा 11-12 अक्टूबर 2019 को हुई थी। उस दौरान वह तमिलनाडु के मामल्लापुरम पहुंचे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत-चीन के दूसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। इससे पहले वर्ष 2018 में दोनों नेताओं की पहली अनौपचारिक बैठक चीन के वुहान में हुई थी।

मामल्लापुरम बैठक के दौरान मोदी और शी ने भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की थी। अब करीब सात साल बाद शी जिनपिंग के भारत दौरे की संभावना ने दोनों देशों के रिश्तों को लेकर नई चचाओं को जन्म दे दिया है।

न्यूज IN ब्रीफ

350 नियम विरुद्ध होर्डिंग पर चलेगा निगम का डंडा

रांची : शहर में नियम विरुद्ध लगाए गए होर्डिंग, विज्ञापन बोर्ड, यूनिपोल, मोनोपोल और अन्य विज्ञापन संरचनाओं के खिलाफ रांची नगर निगम अब व्यापक अभियान चलाएगा। नगर निगम की टीम 10 सितंबर की मध्यरात्रि 12 बजे के बाद विभिन्न इलाकों में चिन्हित विज्ञापन संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई शुरू करेगी। चरणबद्ध अभियान के तहत करीब 350 संरचनाओं को हटाया जाएगा। नगर निगम के अनुसार, पूर्व में सार्वजनिक सूचना जारी कर संबंधित विज्ञापन एजेंसियों और विज्ञापनदाताओं को नियम विरुद्ध संरचनाएं स्वयं हटाने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। इसके बावजूद करीब 350 होर्डिंग, यूनिपोल, मोनोपोल और अन्य विज्ञापन ढांचे अब भी लगे हुए हैं। अब संबंधित पक्षों को अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। निगम नियमानुसार संरचनाओं को हटाने के साथ आवश्यकतानुसार जब्ती की कार्रवाई भी करेगा। निगम ने कहा कि यह कार्रवाई झारखंड उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जा रही है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 19 जून 2026 को नागरिकों के सुरक्षित पैदल आवागमन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिए जाने के मद्देनजर सार्वजनिक मार्गों को अवरोधमुक्त रखना जरूरी है। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य विज्ञापन गतिविधियों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें निर्धारित नियमों के अनुरूप व्यवस्थित करना है। सड़क, फुटपाथ, बिजली के खंभों और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों पर लगाए गए अवैध विज्ञापन ढांचे से आवागमन और सुरक्षा प्रभावित होती है। निगम ने संबंधित एजेंसियों से कार्रवाई शुरू होने से पहले नियम विरुद्ध संरचनाएं स्वयं हटाने की अपील की है। कार्रवाई और उससे होने वाले खर्च की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी या विज्ञापनदाता की होगी।

ट्रांसपोर्ट नगर से शहर में घटेगा भारी वाहनों का दबाव : सुशांत गौरव

रांची : शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम, व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने की दिशा में सुकुरहुटू स्थित नवनिर्मित ट्रांसपोर्ट नगर को महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। बुधवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव के नेतृत्व में रांची नगर निगम, जिला प्रशासन और जुडको के अधिकारियों ने ट्रांसपोर्ट नगर के चरण एक और चरण दो का संयुक्त निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने परिसर की रूपरेखा, प्रवेश और निकास व्यवस्था, पार्किंग, माल चढ़ाने-उतारने के क्षेत्र, आधारभूत सुविधाओं तथा वाहन चालकों और परिवहन व्यवसाय से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नगर आयुक्त ने अधिकारियों को शहर की जरूरत के अनुसार परिवहन क्षेत्रों का वर्गीकरण, मार्ग योजना और अन्य व्यवस्थाएं विकसित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से परामर्श के बाद आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

सुशांत गौरव ने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर के संचालन से शहर की प्रमुख सड़कों पर भारी मालवाहक वाहनों का दबाव कम होगा। इससे जाम की समस्या घटने, आवागमन सुगम होने और सड़क सुरक्षा में सुधार की उम्मीद है। यहां भारी वाहनों की पार्किंग, माल चढ़ाने-उतारने, परिवहन व्यवसाय से जुड़े कार्य और चालकों के ठहरने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर से सुकुरहुटू और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। परिवहन और माल ढुलाई से जुड़े कारोबार के साथ सहायक व्यवसाय विकसित होने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। निरीक्षण में उप नगर आयुक्त रविंद्र कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता मुकेश कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

किसी भी योग्य व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से नहीं छूटेगा : रीमा रेजिना

रांची : बरगाई अंचल में कांके विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 444 से 472 तक विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जारी नोटिस के निवारण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सहायक निर्वाचक निबंध पदाधिकारी रीमा रेजिना लकड़ा के नेतृत्व में संबंधित मतदाताओं के आवेदन और दस्तावेजों की जांच कर उनका त्वरित निष्पादन किया जा रहा है।

बुधवार को बड़ी संख्या में मतदाता आवेदन और जरूरी दस्तावेज लेकर कार्यालय पहुंचे। भीड़ के बावजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने व्यवस्थित तरीके से दस्तावेजों की जांच कर प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान राज कमल सिंह, ताजुद्दीन अंसारी, रूपल भुट कुमार और सदाफ अहमद समेत अन्य सहायकों की भूमिका सराहनीय रही।

रीमा रेजिना लकड़ा ने कहा कि किसी भी योग्य व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से नहीं छूटेगा। उन्होंने नोटिस प्राप्त मतदाताओं से निर्धारित समय-सीमा के भीतर फॉर्म भरकर वैध दस्तावेज जमा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाता किसी अफवाह या भ्रम में न पड़ें। आवेदन या दस्तावेज से संबंधित परेशानी होने पर सीधे कार्यालय से संपर्क कर समस्या का समाधान कराया जा सकता है। प्रशासन सभी योग्य मतदाताओं के दावों का नियमानुसार निवारण सुनिश्चित कर रहा है।

जल बजट से कम किया जा सकता है जल संकट का जोखिम : राजेश्वरी बी

रांची : केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में बुधवार को जल बजट और जल सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से जल-पर्याप्त ग्राम पंचायतों के विकास को लेकर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के दूसरे चरण का उद्घाटन हुआ। नौ से 11 सितंबर तक चलने वाले तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग ने भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से किया है। इसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के पंचायती राज विभागों से 30 प्रतिभागी शामिल हुए हैं।

उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए पंचायती राज मंत्रालय की संयुक्त सचिव पालका साहनी ने कहा कि जल बजट और जल सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से ग्राम पंचायतों की स्थानीय जल परिस्थितियों के आधार पर योजनाएं तैयार करना जरूरी है। मंत्रालय गांवों में जल शक्ति को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है।

मंत्रालय के निदेशक विपुल उज्जवल ने कहा कि जल की उपलब्धता और उसका प्रभावी प्रबंधन ग्राम पंचायतों के सामने बड़ी चुनौती है। सामुदायिक भागीदारी और आपसी सीख के माध्यम से इसका समाधान किया जा सकता है। जल बजट और जल सुरक्षा योजनाएं केवल दस्तावेज नहीं, बल्कि जल संरक्षण और जल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की कार्ययोजना हैं।

पंचायती राज विभाग की निदेशक राजेश्वरी बी. ने कहा कि स्थानीय जल संसाधनों का आकलन कर जल बजट तैयार करने से जल संकट के जोखिम को कम किया जा सकता है। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य देवेंद्र कुमार सिंह ने जल बजट और जल सुरक्षा योजनाओं को ग्राम पंचायत विकास योजना से जोड़ने पर जोर दिया।

पानी टंकी का टावर गिरा, मलबे में दबकर दो मजदूरों की मौत, तीन को किया गया रेस्क्यू

संवाददाता

रांचीः राजधानी रांची में बुधवार शाम पुराने पानी टंकी के टावर को गिराने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। टावर अचानक ढह गया और उसके मलबे में दबकर दो मजदूरों की मौत हो गई। हादसा शाम करीब छह बजे कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित जिला स्कूल परिसर में हुआ। यहां नई पानी टंकी बनाने के लिए पुराने ढांचे को तोड़ने का काम चल रहा था।

हादसे के वक्त पांच मजदूर थे मौके परः अधिकारियों के मुताबिक, जिस समय पुराने टावर को गिराने का काम चल रहा था, उस दौरान मौके पर कुल पांच मजदूर मौजूद थे। टावर अचानक भरभराकर गिर गया और दो मजदूर मलबे में दब गए। वहीं, तीन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

एक शव पहले, दूसरा बचाव अभियान के दौरान मिलाः एएसपी निखिल राय ने बताया कि हादसे में दो मजदूरों की मौत हुई है। टावर गिरने के बाद एक मजदूर का शव तुरंत मलबे से बरामद कर लिया गया था, जबकि दूसरा मजदूर मलबे के नीचे फंस गया था। उसकी तलाश के लिए बचाव अभियान चलाया गया।

एनडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चाः हादसे की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। रांची स्थित 9वीं बटालियन एनडीआरएफ के कमांडेंट मोहम्मद सलीम रईम ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम

घटनास्थल के लिए रवाना हुई। टीम ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया और मलबे में फंसे मजदूर की तलाश की। कमांडेंट ने बताया, ȑहादसे के वक्त यहां पांच लोग थे। इनमें से तीन को सुरक्षित बचा लिया गया। एक शव जिला प्रशासन ने पहले ही बरामद कर लिया था, जबकि दूसरा शव अब बरामद कर लिया गया है। शव को पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

हादसे के कारणों की जांच शुरूः हादसे के बाद जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुराने पानी टंकी के टावर को गिराने के दौरान यह ढांचा अचानक क्यों ढह गया, इसकी जांच की जा रही है। प्रशासन की ओर से हादसे से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जानकारी जुटाई जा रही है।

तीन सहोदर भाइयों को सुनाई 28 साल की सश्रम कारावास की सजा

संवाददाता

चतरा : जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ चतरा पुलिस की कार्रवाई और जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर चतरा व्यवहार न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में तीन सहोदर भाइयों को कड़ी सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शम्भु लाल साव के न्यायालय ने अफीम और डोडा की अवैध तस्करी से जुड़े मामले में तीनों भाइयों को अलग-अलग सजा सुनाते हुए कुल 28 वर्ष का सश्रम कारावास और 5।25 लाख रुपये का जुमार्ना लगाया है।मामला 7 जून 2023 का है। राजपुर पुलिस ने थाना क्षेत्र के बनियाबांध गांव निवासी मुंशी यादव, पुन यादव उर्फ पुनाई यादव और रामवृक्ष यादव उर्फ वृक्ष यादव तीनों पिता स्वर्गीय डाहो यादव उर्फ ननकु यादव को अवैध रूप से अफीम डोडा और अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस छापेमारी के दौरान मुंशी यादव के घर से सात बोरियों में 84।600 किलोग्राम डोडा तथा 4।600 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद हुई थी।वहीं पुन यादव उर्फ पुनाई यादव के घर से पांच बोरियों में 99।600 किलोग्राम डोडा बरामद किया गया। इसके अलावा रामवृक्ष यादव उर्फ वृक्ष यादव के घर से दो प्लास्टिक बोरियों में 40।500 किलोग्राम डोडा बरामद किया गया।पुलिस छापेमारी की भनक लगते ही तीनों आरोपी अपने-अपने घरों से फरार हो गए थे। बाद में तीनों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ी और सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई। न्यायालय ने मुंशी यादव को 14-14 वर्ष की दो सजाओं के तहत कुल 28 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 3 लाख रुपये जुमार्ना लगाया है।जुमार्ना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त तीन वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा।पुन यादव उर्फ पुनाई यादव को 14 वर्ष का सश्रम कारावास और 1.50 लाख रुपये जुमार्ना लगाया गया है। जुमार्ना नहीं देने पर अतिरिक्त डेढ़ वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा।

वहीं रामवृक्ष यादव उर्फ वृक्ष यादव को 7 वर्ष की सश्रम कारावास और 75 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जुमार्ना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त छह माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुबोध कुमार मिश्रा एवं प्रदीप कुमार सिन्हा ने दलीलें पेश कीं। जबकि राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।

किशुनपुर में भीषण सड़क हादसा

खड़े ट्रक में घुसी कार, एक युवक की दर्दनाक मौत, तीन गंभीर

संवाददाता

चतरा : जिले से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। बुधवार की देर रात सदर थाना क्षेत्र के किशुनपुर में एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और इसमें सवार एक 28 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के अनुसार, यह हादसा रात करीब 11:30 बजे लखन मिस्त्री के घर के पास हुआ। किशुनपुर निवासी सरयू राणा के बेटे बसंत राणा अपनी बोलेनो कार से बधार की ओर से लौट रहे थे। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। हादसा इतना भयानक था कि कार का अगला

हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। बाद में जेसीबी की मदद से कार को ट्रक से अलग कर बाहर निकाला गया।इस दर्दनाक हादसे में बसंत राणा ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वहीं, कार में सवार उपेन्द्र राणा, रामदेव राणा और गुड्डू राणा गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक की लहर है। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन से मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने और सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से खड़े किए जाने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

कथित प्रेम प्रसंग को लेकर टंडवा के सिद्पा में ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव

संवाददाता

चतरा : जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के सिद्पा गांव में दो समुदायों के बीच कथित प्रेम प्रसंग की घटना में युगल को छुड़ाने को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव की घटना में टंडवा थाना प्रभारी पप्पु शर्मा का सर फट गया।घायल थाना प्रभारी को एनटीपीसी के संजीवनी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के पश्चात हजारीबाग रेफर किया गया है। घटना की सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक अनिमेष नैथानी और चतरा के एसडीपीओ सन्नी वर्धन मौके पर पहुंचे। एसपी के निर्देश पर पहुंची अतिरिक्त पुलिस बल ने उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग एवं हवा में चार राउंड गोली चलाई।इस दौरान दोनों को बरामद कर थाना पहुंचाया।

टंडवा के सीओ गौरव राय के आवेदन पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी संपति की तोड़फोड़,दो पुलिस पदाधिकारियों समेत

अन्य पुलिस कर्मियों पर हमला करने का मामला दर्ज किया गया है। सीओ के आवेदन पर पांच नामजद और 300 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। वहीं महिला ने स्थानीय थाना में गांव के कुछ लोगों पर षड्यंत्र के तहत बदनाम करने का आरोप लगाते हुए घर में तोड़फोड़ का आरोप लगाया गया है। आवेदन में कहा गया है कि युवक के साथ उसका किसी भी प्रकार का अवैध रिश्ता नहीं है। युवक के साथ उसका मवेशियों की खरीद फरोख्त को लेकर पैसे के लेनदेन का मामला था। पैसे को मांगने के लिए अक्सर वह घर पर आता था। इसी बीच गांव के कुछ युवकों ने जबरदस्ती हम दोनों को कमरे में बंद कर दिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी। आवेदन ने गांव के पांच छः युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। एसपी अनिमेष नैथानी ने बताया कि महिला के आवेदन के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ कांड संख्या 206/26 एवं सीओ गौरव कुमार की ओर से कांड संख्या 207/26 के तहत 37 नामजद और 300-400 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

वैष्णव दुर्गा मंदिर पूजा समिति की बैठक में दुर्गा पूजा पर विचार विमर्श

लातेहार : शहर के थाना चौक इलाके में अवस्थित श्री वैष्णव दुर्गा मंदिर समिति की बैठक अरूण कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गयी । बैठक में दुर्गा पूजा- 2026 की तैयारियों व कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर विचार विमर्श किया गया।

बैठक में संरक्षक विनोद कुमार साहू व अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने सामुहिक रूप से मिल कर आयोजन को सफल बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोई भी बड़ा अनुष्ठान बिना सामुहिक सहयोग के पूरा नहीं होता है। उन्होने कहा कि श्री वैष्णव दुर्गा मंदिर की अपनी एक प्रतिष्ठा है और उस प्रतिष्ठा को बरकरार रखना है। बैठक पिछले वर्ष दुर्गा पूजा में किये गये आयोजनों पर चर्चा की गयी और इस वर्ष उसे और अधिक भव्य रूप से कराने का निर्णय लिया गया। आकर्षक मंच सज्जा के अलावा मंदिर के बाहरी परिसर के साज सजावट पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में संरक्षक अभिनदन प्रसाद, उपाध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, कन्हाई प्रसाद अग्रवाल, बद्री प्रसाद, अशोक दास, सचिव आशीष टैगोर, सह सचिव रंजीत कुमार व रविंद्र प्रजापति, कोषाध्यक्ष राजू रंजन सिंह, ओम प्रकाश प्रसाद (राजू), दीपक विश्वकर्मा, संजय प्रसाद (गुड्डू), सतीष कुमार, पंकज कुमार व पारितोष ठाकुर व अन्य मौजूद थे।

राज्य में एक अक्तूबर से लागू होगा स्मार्ट पीडीएस

छह महीने राशन नहीं लिया तो कार्ड होगा निष्क्रिय, ई-केवाईसी जरूरी

संवाददाता

रांची : झारखंड खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग एक अक्तूबर से नई स्मार्ट-पीडीएस प्रणाली लागू कर रहा है। इस व्यवस्था के माध्यम से निष्क्रिय राशन कार्डों तथा दोहरी प्रविष्टि वाले लाभार्थियों की स्वतः पहचान कर उन्हें निष्क्रिय किया जाएगा। प्रशासन ने जिले के सभी राशन कार्डधारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने कार्ड से जुड़ी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। पात्र लाभार्थियों को पारदर्शी और सुचारू रूप से अनाज वितरण सुनिश्चित करने के लिए विभाग राशन कार्डों का नियमित सत्यापन और ई-केवाईसी अभियान चला रहा है।

छह महीने राशन न लेने पर कार्ड होगा निष्क्रियः जिन राशन कार्डों के जरिये पिछले छह महीने से खाद्यान्न का उठाव नहीं हुआ है, विभाग उन्हें हर महीने की 21 तारीख को चिह्नित कर निष्क्रिय करेगा। इसके बाद, अगले महीने की 1 तारीख से संबंधित राशन कार्ड स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा। प्रशासन ने सभी पात्र राशन कार्डधारियों से कहा है कि वे निकटतम उचित मूल्य की दुकान से नियमित रूप से खाद्यान्न प्राप्त करें। कार्डधारक राशन दुकानदारों से मिलकर अपने राशन कार्ड की वर्तमान स्थिति की जानकारी भी ले सकते हैं।

तीन महीने के भीतर ई-केवाईसी कराना अनिवार्यः निष्क्रिय श्रेणी में डाले गए राशन कार्डों को पुनः

क्रियाशील कराने के लिए विभाग लाभार्थियों को तीन महीने की समय-सीमा दे रहा है। इस तय समय में कार्डधारियों को ई-केवाईसी और आवश्यक सत्यापन कराना होगा। यदि तय अवधि के भीतर सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तो विभाग संबंधित राशन कार्ड को स्थायी रूप से रद्द कर देगा। जिन लाभार्थियों का कार्ड निष्क्रिय हो चुका है या ऐसी संभावना है, वे जल्द अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान या विभागीय केंद्र पर जाकर ई-केवाईसी करा लें।

दोहरी प्रविष्टि वाले कार्डों पर कार्रवाईः विभाग आधार आधारित मिलान प्रक्रिया के जरिये दोहरी प्रविष्टि वाले लाभार्थियों की पहचान भी कर रहा है। ऐसे डुप्लीकेट लाभार्थियों के नाम अस्थायी रूप से निष्क्रिय किए जा रहे हैं। विभाग इस बात की सूचना परिवार के मुखिया के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेज रहा है। यदि तय समय में ई-केवाईसी और सत्यापन नहीं कराया जाता, तो लाभार्थी का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा।

एमईएस में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी

मेट्रो रेज

रांची: राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में सेना के प्रतिष्ठित विभाग मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस (एमईएस) में नौकरी दिलाने के नाम पर एक बड़े फर्जीवाड़े का पदार्फाश हुआ है। जालसाजों ने सरकारी नौकरी का झांसा देकर एक युवक से लाखों रुपये ठग लिए। पीड़ित की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा है।

खेलगांव क्षेत्र से धराया आरोपीः मामले की गंभीरता को देखते हुए नामकुम थाना पुलिस ने तत्काल टीम का गठन किया और खेलगांव पुलिस के सहयोग से संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया। पुलिस ने खेलगांव इलाके से मुख्य आरोपी गौतम सिंह को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल उसे थाने लाकर कड़ाई से पूछताछ की जा रही है।

फर्जी नियुक्ति पत्र और गिरोह का संदेहः सूत्रों के अनुसार, आरोपी युवक को सेना के इंजीनियरिंग विभाग में पक्की नौकरी का लालच देकर अपने जाल में फंसाया था। ठगी का अहसास होने के बाद पीड़ित ने नामकुम थाने में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस को आशंका है कि इस फर्जीवाड़े में गौतम सिंह के साथ कोई बड़ा संगठित गिरोह भी शामिल हो सकता है, जो बेरोजगार युवाओं को अपना शिकार बनाता है।

पुलिस की जांच जारी, जल्द होगा खुलासाः मामले पर फिलहाल पुलिस का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी खुलकर बोलने से बच रहा है। नामकुम पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों और ठगी की कुल रकम का पता लगाया जा रहा है। पुलिस आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस पूरे मामले का विस्तृत खुलासा कर सकती है।

चाहत कौसर को डॉक्टरेट की उपाधि

मेट्रो रेज

रांची: जाने-माने समाजसेवी व एसबीआई से सेवानिवृत्त नफीसुल आबदीन की बेटी चाहत कौसर को रांची विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग से डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। उन्होंने "Research studies on the efficacy of some anti-cancer ethno-medical plants against colon cancer cell lines and unravelling the molecular mechanism" विषय पर शोध किया।

चाहत ने गुरु नानक हाई स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा के बाद विमेंस कॉलेज से बीएससी (बायोटेक्नोलॉजी) और रांची विश्वविद्यालय से एमएससी (बायोटेक्नोलॉजी) की। वर्तमान में वह एनआईटी राउरकेला में टेक्निकल फैकल्टी के पद पर कार्यरत हैं।

उनकी उपलब्धि पर परिवार, शुभचिंतकों और मॉर्निंग ग्रुप के सदस्यों ने बधाई दी। सरपरस्त मोहम्मद हलीमुद्दीन, अध्यक्ष अकील-उर-रहमान और मरहबा ह्यूमन सोसाइटी के सेक्रेट्री नेहाल अहमद ने कहा कि चाहत की सफलता समाज की छात्राओं के लिए प्रेरणादायक है।

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए तीन नई डिजिटल पहल शुरू

मेट्रो रेज

रांची: वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय लोहिया ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए तत्काल रुपे कार्ड और व्यापारी यूपीआई क्यूआर जारी करने वाले ओपन-सोर्स एटीएम, केसीसी व पीएम मुद्रा योजना के लिए यूपीआई पर क्रेडिट लाइन तथा एईपीएस के तहत थ्री-पार्टी नकद जमा सुविधा शुरू की है। ओपन-सोर्स एटीएम से ग्राहक बैंक शाखा जाए बिना तत्काल रुपे डेबिट, क्रेडिट और एनसीएमसी कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। यूपीआई पर क्रेडिट लाइन के तहत पात्र केसीसी और मुद्रा लाभार्थी यूपीआई से अपनी स्वीकृत ऋण सीमा का इस्तेमाल कर सकेंगे। वर्तमान में 7.7 करोड़ से अधिक सक्रिय केसीसी खातों में 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक की ऋण सीमाएं हैं, जबकि पीएम मुद्रा योजना के तहत 57 करोड़ से अधिक ऋणों की राशि 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। एईपीएस थ्री-पार्टी नकद जमा सुविधा से ई-केवाईसी पंजीकृत व्यक्ति सहभागी केंद्र संचालकों के जरिए लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे नकद जमा कर सकेंगे।

राजधानी रांची में भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा कल

बापू वाटिका से अल्बर्ट एक्का चौक तक होगा विशाल पैदल मार्च

मेट्रो रेज

रांची: राज्य की नियुक्ति प्रक्रिया में व्याप्त धांधली, अनियमितता व भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा आज, गुरुवार शाम राजधानी रांची पहुंचेगी। इसके बाद कल 11 सितंबर को राजधानी की सड़कों पर छात्रों का विशाल पैदल मार्च निकाला जाएगा।

कार्यक्रम की शुरूआत बापू वाटिका, मोरहाबादी से होगी, जहां छात्रों का जुटान होगा। इसके बाद बापू वाटिका से करमटोली चौक, लालपुर चौक होते हुए भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल, कोकर तक पदयात्रा की जाएगी। समाधि स्थल पर भगवान बिरसा मुंडा को माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी।

इसके उपरांत यात्रा जेल मोड़ होते हुए राजधानी के हृदयस्थल अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचेगी। यहां छात्रों द्वारा सरकार की युवा व छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया जाएगा। इस दौरान लगभग सात किलोमीटर की पदयात्रा कि दुरी तय की जाएगी।

भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि राज्य की भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि ह्वयह महज एक यात्रा नहीं, बल्कि झारखंड के युवाओं के सुरक्षित भविष्य, सम्मान और अधिकार की लड़ाई है। राज्य के अलग-अलग हिस्सों से उठ रही युवाओं की आवाज अब राजधानी रांची में बुलंद होगी।

बताते चलें कि 24 अगस्त 2026 को दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जन्मस्थली नेमरा, रामगढ़ से शुरू हुई भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा राज्य के विभिन्न जिलों से होते हुए अब राजधानी रांची पहुंचकर विधिवत समापन किया जाएगा।

रिम्स डेंटल कॉलेज में पहली बार शुरू हुआ एमडीएस कोर्स

रांची: रिम्स डेंटल कॉलेज में पहली बार मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (एमडीएस) कोर्स शुरू किया जा रहा है। इसी शैक्षणिक सत्र से एमडीएस में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्टेट कोटा से आवंटित एमडीएस की सभी 13 सीटों पर नामांकन हो चुका है, जबकि सेंट्रल कोटा की 14 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया जारी है।

सभी 9 दंत चिकित्सा विभागों में शुरू होंगे एमडीएस कोर्सः रिम्स डेंटल कॉलेज के सभी नौ दंत चिकित्सा विभागों में एमडीएस कोर्स शुरू किया जा रहा है। प्रत्येक विभाग में तीन-तीन एमडीएस सीटें निर्धारित की गयी हैं। डेंटल कॉलेज में बीडीएस और एमडीएस विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन कोर्स भी 15 सितंबर से शुरू करने की तैयारी है।

डीसीआई ने इसी सत्र से दी है नामांकन की अनुमतिः डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई) ने रिम्स डेंटल कॉलेज को इसी शैक्षणिक सत्र से एमडीएस में नामांकन लेने की अनुमति दी है। इसके साथ ही राज्य के सरकारी डेंटल कॉलेज में पहली बार एमडीएस की पढ़ाई शुरू होने का रास्ता साफ हुआ है। वहीं, रिम्स डेंटल कॉलेज में बीडीएस की 63 सीटों पर भी नामांकन जारी है। इनमें स्टेट कोटा से 54 सीटों पर नामांकन लिया जाना है, जबकि शेष सीटें सेंट्रल कोटा से आवंटित की गयी है।

लोहरदगा सदर अस्पताल के एम्बुलेंस ड्राइवर और नाइट वॉचमैन होंगे नियमित, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

संवाददाता

रांची/लोहरदगाः झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को लोहरदगा सदर अस्पताल में पिछले 10 साल से अस्थायी नौकरी करने वाले एम्बुलेंस चालक और नाइट वॉचमैन की रिट याचिका पर सुनवाई की गई। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की पीठ ने रिट याचिका स्वीकार करते हुए संबंधित प्राधिकार को 12 सप्ताह के भीतर नियमितीकरण पर आवश्यक कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया। कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग एजेंसी के अधीन काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।

आउटसोर्सिंग के खिलाफ पहुंचे थे हाईकोर्टः मामला उन कर्मचारियों से जुड़ा था जो लंबे समय से सदर अस्पताल, लोहरदगा में एम्बुलेंस चालक और नाइट वॉचमैन के रूप में कार्यरत हैं। याचिकाकताओं का कहना था कि करीब एक दशक तक लगातार सेवा देने के बावजूद उन्हें उनके मौजूदा कार्य से हटाकर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से काम कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। कर्मचारियों का आरोप था कि उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध आउटसोर्सिंग एजेंसी के अधीन काम करने के लिए बाध्य किया जा रहा था।

याचिका में क्या थी मुख्य मांगः याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से आग्रह किया था कि उनकी लंबी और निरंतर सेवा अवधि को देखते हुए नियमितीकरण पर विचार किया जाए। साथ ही यह भी मांग की गई कि उन्हें आउटसोर्सिंग एजेंसी के अधीन काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। उनका कहना था कि वर्षों से अस्पताल में सेवा देने के बाद भी उनकी स्थिति अस्थायी बनी हुई थी।

हाईकोर्ट ने पहले दिया था अंतरिम संरक्षण : मामले की शुरूआती सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को अंतरिम राहत भी दी थी। अदालत ने संबंधित विभाग और प्राधिकार को निर्देश दिया था कि याचिकाकताओं को आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। इस अंतरिम आदेश के कारण कर्मचारियों को तत्काल राहत मिली और बाद में मामले की विस्तृत सुनवाई हुई।

सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसलाः सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति दीपक रोशन की पीठ ने रिट याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं के नियमितीकरण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई 12 सप्ताह के भीतर पूरी की जाए। यह आदेश संबंधित प्राधिकार को समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने की जिम्मेदारी देता है।

रांची में तीन बड़े फ्लाइओवर का टेंडर फाइनल, अक्तूबर से शुरू होगा निर्माण कार्य

संवाददाता

रांची: राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में तीन बड़ी योजनाओं का रास्ता साफ हो गया है। करमटोली-चिरौंदी, अरगोड़ा-चापुटोली और हरमू फ्लाइओवर का टेंडर फाइनल हो गया है। इसके लिए दो माह पूर्व टेंडर निकाला गया था। तीनों योजनाओं के लिए अलग-अलग कंपनियों का एल-वन चयन किया गया है। अब रेट नेगोशिएशन के बाद कंपनियों को काम आवंटित किया जाएगा। अक्तूबर से तीनों फ्लाइओवर का निर्माण शुरू कराने की तैयारी है।

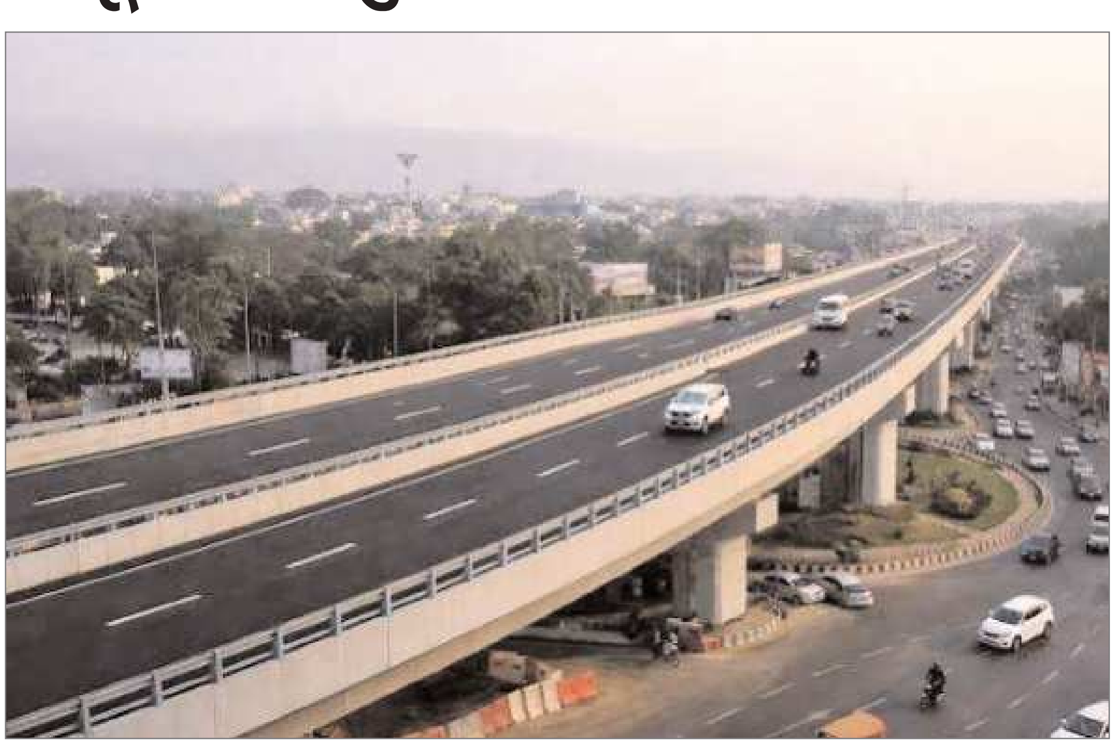

तीन कंपनियों का हुआ चयनः करमटोली-चिरौंदी फ्लाइओवर के लिए शिवालया कंस्ट्रक्शन कंपनी, अरगोड़ा-चापुटोली फ्लाइओवर के लिए दिनेश चंद्र आर अग्रवाल इंफ्राकॉन कंपनी और हरमू फ्लाइओवर के लिए हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (एचसीसी), मुंबई का एल-वन चयन हुआ है।

तीनों फ्लाइओवर का निर्माण स्टेट हाइवे ऑथोरिटी ऑफ झारखंड (साज) की ओर से कराया जाएगा। इनका निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड में होगा। इस व्यवस्था में चयनित कंपनी ही डिजाइन से लेकर निर्माण तक का काम करेगी। जरूरत पड़ने पर कंपनी डिजाइन में मामूली संशोधन का प्रस्ताव भी दे सकेगी।

इन योजनाओं पर होना है काम

हरमू फ्लाइओवरः हरमू फ्लाइओवर सहजानंद चौक के पहले से शुरू होकर हरमू रोड होते हुए रातू रोड को क्रॉस करेगा और कांके रोड स्थित जज कॉलोनी तक जाएगा। इसकी लंबाई करीब 3.5 किमी होगी। इस योजना के लिए दोबारा टेंडर किया गया है और इस बार 326.61 करोड़ रुपए की योजना का टेंडर जारी हुआ था। फ्लाइओवर पर सहजानंद चौक की ओर से आने वाले वाहनों के लिए रातू रोड जाने की अलग व्यवस्था होगी। इसके लिए गोशाला के सामने उतरने की व्यवस्था की जाएगी।

अरगोड़ा फ्लाइओवरः अरगोड़ा चौक फ्लाइओवर के लिए 223.14 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया था। यह हरमू रोड में काव्स रेस्टोरेंट के पास से शुरू होकर डिबडीह ब्रिज के पहले तक बनेगा। इसके अलावा अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ की ओर चापुटोली और अशोक नगर रोड नंबर 3 तक भी फ्लाइओवर का निर्माण होगा। इसमें राउंड अबाउट की व्यवस्था होगी। इससे चारों तरफ से आने-जाने वाले वाहनों को सुविधा मिलेगी। इस फ्लाइओवर की कुल लंबाई 3.804 किमी होगी।

करमटोली फ्लाइओवरः करमटोली फ्लाइओवर को करमटोली चौक से साइंस सिटी यानी चिरौंदी तक बनाया जाएगा। इसकी कुल लंबाई 3.216 किमी होगी। इसमें मुख्य फ्लाइओवर की लंबाई 2.7 किमी होगी, जबकि 0.52 किमी लिंक रोड मोरहाबादी के लिए होगा। इस लिंक रोड का इस्तेमाल मोरहाबादी मैदान और स्टेडियम की ओर से आने वाले लोग कर सकेंगे। इस परियोजना के लिए 351 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया था।

एचसीसी ने कई बड़ी परियोजनाओं पर किया है कामः हरमू फ्लाइओवर के निर्माण के लिए चुनी गई हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (एचसीसी) मुंबई की बड़ी निर्माण कंपनियों में शामिल है। कंपनी ने बांद्रा-वर्ली सी लिंक सहित कई बड़ी परियोजनाओं पर काम किया है।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग भवन प्रमंडल संख्या–1, रॉंची

अति अल्पकालीन निविदा/कोटेशन आमंत्रण सूचना– 47/2026–27

1. विज्ञापनदाता का नाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल संख्या–1,रॉंची।
2. परिमाण विपत्र बिक्री करने की तिथि एवं समय : दिनांक 16.09.2026 को 1.00 (एक) बजे अपराह्न तक।
3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय : दिनांक 18.09.2026 को 3.00(तीन) बजे अपराह्न तक।
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 18.09.2026 को 3.30(साढे तीन) बजे अपराह्न।
5. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान : अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, छोटानागपुर भवन अंचल–1, रॉंची के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा नगर नियंत्रण कक्ष, रॉंची एवं कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल संख्या–1, रॉंची के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा नगर नियंत्रण कक्ष, रॉंची।
6. निविदा प्राप्ति का स्थान : नगर नियंत्रण कक्ष रॉंची।
7. निविदा खोलने का स्थान : अधोहस्ताक्षरी का कार्यालय।
8. कार्यों का विवरण :

क्र	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य समाप्ति की तिथि
1	Renovation of New Judge Bungalow No-1 (Six Set) with Painting work and Provision of Shed on First Floor, Open terrace at Doranda, Ranchi (High Court Pool)	3797000	76000	5000	Two Month
2	Renovation of Govt. Gazetted Quarter No-A-6/13, 13 Set at Doranda, Ranchi	1940800	39000	5000	Two Month

नोट :– निविदा की शर्तें कार्यालय के सूचना पट पर देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्ल संख्या–1, रॉंची

PR 389387 (Building)26-27*D

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल संख्या–2, रॉंची
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–50/2026–27

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं0–2, रॉंची।
2. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि एवं समय : दिनांक 29.09.2026 को 1.00 बजे अपराह्न तक
3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय : दिनांक 30.09.2026 को 3.00 बजे अपराह्न तक।
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 30.09.2026 को 3.30 बजे अपराह्न।
5. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान : 1) अधीक्षण अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, भवन अंचल सं0–2, रॉंची के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा 2) कार्यपालक अभियन्ता,भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं0–2, रॉंची के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा नगर नियंत्रण कक्ष रॉंची।
6. निविदा प्राप्ति का स्थान : नगर नियंत्रण कक्ष रॉंची, कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं0–2, रॉंची के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा।
7. निविदा खोलने का स्थान : अधोहस्ताक्षरी का कार्यालय
8. कार्य की विवरणी :

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रू.)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रू.)	अग्रधन की राशि (रू.)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	Renovation of Room No. -152 Occupied by Kala Sanskriti Kendra at Old Vidhan Sabha Bhawan Campus, Russian Hostel, Dhurwa, Ranchi	2,38,800.00	500.00	5000.00	1 Month
2	Renovation of "B" Type Qtr. No. -2548 (F.Fl.) in Sector -2 at HEC, Dhurwa, Ranchi	3,99,100.00	750.00	8000.00	1 Month
3	Renovation of Room No. -05 (Cell, Hon'ble Minister, Water Resources & Minority Welfare Department) at Ground Floor and Room No. -247 (OSD to Hon'ble Minister, Department of Scheduled Tribe, Scheduled Caste, Minority and Backward Class Welfare) at 2nd Floor of Project Building, HEC, Dhurwa, Ranchi	34,36,800.00	5000.00	69000.00	1 Month
4	Renovation of Qtr. No. -04 Located at Doctor's Colony, Bariatu, Ranchi	18,38,400.00	5000.00	37000.00	2 Months

नोट :निविदा की शर्तें http://www.jharkhand.gov.in एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखी जा सकती है।

कार्यपालक अभियन्ता
भवन निर्माण विभाग भवन प्रमण्डल
संख्या–2, रॉंची

PR 389341 Building(26-27)D

सूक्ति

सबसे प्रेम करो, कुछ पर विश्वास करो
अन्याय किसी के साथ मत करो : शेक्सपियर

लालच व लापरवाही की जड़ें काटने से ही थमेंगे हादसे

लालच और लापरवाही की इंतहा में निर्दोषो की जान चली जाए तो भी जिम्मेदारों ने शायद हादसों से सबक नहीं लेने की कसम खा रखी है। मध्यप्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से हुई मौतें हो या फिर देश की राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पीजी की इमारत ढहने से हुआ हादसा, दोनों के लिए भ्रष्ट व लापरवाह तंत्र जिम्मेदार है। दोनों में ही लालच का सबसे बड़ा योगदान है। हां, हर हादसे के बाद हमारे यहां लकीर पीटने का काम जरूर होता है। इसलिए मध्यप्रदेश में शराब दुकानें सील कर आबकारी महकमे के कुछ अफसरों पर निलंबन की कार्रवाई हुई है वहीं, दिल्ली में नगर निगम के पांच अफसरों को हादसे के लिए जिम्मेदार मानते हुए निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि अब ऐसी नीति बनाई जाएगी, जिसके तहत सार्वजनिक उपयोग के लिए बनी इमारतों की समय-समय पर सुरक्षा जांच होगी।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दोनों ने ही ऐलान किया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये लोग बख्शे जाने योग्य भी नहीं हैं लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ निलंबन की कार्रवाई ही पर्याप्त है। क्या उन अफसरों को घर पर नहीं बैठा देना चाहिए था जिनकी लापरवाही ने सागर में जहरीली शराब की बिक्री होने दी और सस्ती के लालच में आकर इसे पीने वाले काल का ग्रास बन गए। क्या उनकी सेवा से बर्खास्तगी नहीं होनी चाहिए, जो चांदी की खनक के आगे बरसात के दौर में असुरक्षित इमारत में बेसमेंट खुदाई को लेकर आंखों पर पट्टी बांधे रहे। जहरीली शराब और इमारत ढहने से मौत के मामले हो या फिर बहुमंजिला इमारतों में आग लगने की घटनाएं। सबकी वजह जानने को लेकर जितने भी सवाल उठते हैं उनका एक ही जवाब है- जिम्मेदारों का लापरवाह रवैया। यह बात सच है कि सुरक्षा मानकों की पालना हर जगह होनी चाहिए। वहीं इस बात की सतत निगरानी भी जरूरी है कि कहीं नियम-कायदों की अवहेलना तो नहीं हो रही। चिंता का विषय यही है कि 'आग लगने पर कुआं खोदने' की प्रवृत्ति ही सिस्टम में इस तरह घुस गई है कि सारे नियम-कायदे कोई हादसा होने के बाद ही याद आने लगते हैं। जब जिम्मेदारी तय करने की बारी आती है तो समूचा भ्रष्ट तंत्र सुरक्षा कवच बनकर खड़ा हो जाता है। ज्यादा ही शोरगुल हुआ तो कुछ लोगों के नाम पर निलंबन के छींटे डाल दिए जाते हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या जिम्मेदार अफसरों और कार्मिकों के निलंबन की कार्रवाई ही काफी है। रिश्वत के दम पर अवैध काम करने वाले क्यों बच जाते हैं? हादसों में दोषियों पर सीधे आपराधिक कार्रवाई जरूरी है। सजा भी ऐसी दी जानी चाहिए, जो नजीर बने। क्योंकि जिन्हें 'भ्रष्टाचार की गंगा' में स्नान करने की आदत पड़ गई वे नहीं सुधरेंगे। सिस्टम में पसरी लालच और लापरवाही की जड़ें काटकर ही हादसों की रोकथाम संभव है।

खेती में कीटनाशक नीति पर पुनर्विचार का समय

भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले किसान की सुरक्षा को लेकर सामने आए आंकड़े किसी भी संवेदनशील समाज को झकझोरने के लिए काफी हैं। पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क के हालिया अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में कीटनाशक विषाक्तता से होने वाली करीब 11 हजार मौतों में से 60 प्रतिशत भारत में होती हैं। अध्ययन बताता है कि दुनिया के करीब 93.4 करोड़ किसानों और कृषि श्रमिकों में से 43.3 करोड़ यानी लगभग 46 प्रतिशत हर साल किसी न किसी रूप में कीटनाशक के जहर का शिकार होते हैं। चिंता की बात यह भी है कि 2023 में विश्व भर में करीब 38 लाख टन कीटनाशकों का इस्तेमाल हुआ, जो 1990 की तुलना में लगभग दोगुना है। हरित क्रांति के बाद से उत्पादकता बढ़ाने की होड़ में हमने रासायनिक निर्भरता को लगातार बढ़ाया लेकिन इस्तेमाल करने वालों की सुरक्षा की उतनी ही अनदेखी की जाती रही।

भारत में यह संकट इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि यहां छोटे और सीमांत किसान, जिनकी संख्या देश में सबसे अधिक है, अक्सर बिना उचित प्रशिक्षण, बिना सुरक्षा उपकरणों और बिना किसी निगरानी के कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं। दस्ताने, मास्क या सुरक्षा चश्मे जैसी बुनियादी सावधानियां तो दूर, कई बार किसानों को यह भी नहीं पता होता कि किस रसायन की कितनी मात्रा सुरक्षित है। खेतों में नंगे हाथों से कीटनाशक घोलना, हवा की दिशा का ध्यान न रखते हुए छिड़काव करना और छिड़काव के तुरंत बाद उन्हीं कपड़ों में परिवार के बीच लौट आना- ये दृश्य हमारे ग्रामीण इलाकों में आम हैं। लंबे समय तक कीटनाशकों के संपर्क से पार्किंसन जैसी गंभीर बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। यह आने वाली पीढि ?ों के स्वास्थ्य से जुड़ा दीर्घकालिक संकट है। आखिर जिम्मेदारी किसकी है? यह ठीक है कि किसान संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने समय-समय पर सुरक्षित कीटनाशक इस्तेमाल को लेकर जागरूकता अभियान चलाए हैं, लेकिन यह प्रयास तब तक अधूरा रहेगा जब तक सरकार इसे सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं बनाती। पहली आवश्यकता इस बात की है कि सभी किसानों को कीटनाशक के सुरक्षित इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया जाए। दूसरा, सुरक्षा उपकरण जैसे दस्ताने, मास्क और चश्मे सब्सिडी दरों पर या मुफ्त उपलब्ध कराए जाएं, जैसे बीज और उर्वरक पर सब्सिडी दी जाती है। तीसरा, अत्यधिक विषैले व प्रतिबंधित श्रेणी के कीटनाशकों की बिक्री पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि भारत में आज भी कई ऐसे रसायन खुलेआम बिकते हैं जिन पर विकसित देशों में पहले ही प्रतिबंध लग चुका है।सबसे अहम बात तो यह है कि कीट प्रंबधन के लिए जैविक तरीकों पर निर्भरता बढ़ाने के उपाय कारगर हों। सिक्किम जैसे राज्यों ने पूर्ण जैविक खेती की दिशा में जो कदम उठाए हैं, वे बताते हैं कि रासायनिक निर्भरता से मुक्ति असंभव नहीं है।

विफलता से ज्यादा खतरनाक है विफल महसूस करना

मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए देशभर में नीट यूजी 2026 परीक्षा में लगभग 23 लाख विद्यार्थी अपने सपनों को पूरा करने के लिए शामिल हुए। वे बच्चे जो इस परीक्षा में चयनित हुए उनकी संख्या का हिस्सा उन बच्चों की संख्या की तुलना में नगण्य है, जो किसी कारणवश चयन सूची से बाहर हुए या लोगों के अनुसार विफल हुए। विफल होना और विफल महसूस करना, दोनों अलग अलग परिस्थितियां हैं। असल में कोई एक परीक्षा जिंदगी की दिशा और दशा तय नहीं कर सकती है। वे बच्चे जो इस परीक्षा में विफल रहे वे न जाने किस क्षेत्र में अद्भुत करेंगे, बस उनको उनकी प्रतिभा के अनुसार मौका मिले।

डॉ पीएल भालोठिया

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं तनाव मुक्त माहौल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 पेश किया था। केंद्र एवं और राज्यों की सरकारें भी इस दिशा में काम कर रही हैं। सरकार के प्रयास ऐसे समय में हो रहे हैं, जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की आत्महत्या की बढ़ती संख्या के कारण यह चिंता का विषय बनता जा रहा है। एक तरफ जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए स्कूली शिक्षा से अलग कोचिंग संस्थानों का चलन बढता जा रहा है वहीं ऐसे माहौल में कोचिंग संस्थानों को युवाओं की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए कठघरे में खड़ा किया जा रहा है। पर क्या समस्या का सिर्फ यही पहलू है, जो हमें दिख रहा है या इससे इतर भी कोई बात है? यह सरकारों एवं सामाजिक संस्थाओं को सोचने की महती आवश्यकता है।

मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए देशभर में नीट यूजी 2026 परीक्षा में लगभग 23 लाख विद्यार्थी अपने सपनों को पूरा करने के लिए शामिल हुए। वे बच्चे जो इस परीक्षा में चयनित हुए उनकी संख्या का हिस्सा उन बच्चों की संख्या की तुलना में नगण्य है, जो किसी कारणवश चयन सूची से बाहर हुए या लोगों के अनुसार विफल हुए। विफल होना और विफल महसूस करना, दोनों अलग अलग परिस्थितियां हैं। असल में कोई एक परीक्षा जिंदगी की दिशा और दशा तय नहीं कर सकती है। वे बच्चे जो इस परीक्षा में विफल रहे वे न जाने किस क्षेत्र में अद्भुत करेंगे, बस उनको उनकी प्रतिभा के अनुसार मौका मिले। ऐसे में जब विद्यार्थी वर्ग के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रतिस्पर्धा बहुत चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या हर परीक्षा को और मुश्किल बनाती जा रही है। विद्यार्थियों की प्रतिभा एवं सफलता को सिर्फ अंकों से मापने का जो दौर चल रहा है वह इस स्थिति को और भी विकट बना रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं का परिणाम बच्चों की मेहनत एवं उसके आकलन की ऐसी दौड़ है, जिसमें अभिभावक अपने सपनों को सच होते देखना चाहते हैं। अंको के इस खेल में अपने आप को आगे रखने की इस दौड़ में कुछ बच्चे भावनात्मक चोटिल भी हो रहे हैं। चोटिल होना उतना पीड़ादायक नहीं है जितना उस चोट की अनदेखी करना। ये परिस्थितियां बच्चों में बढती मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं की तरफ इशारा कर रही हैं। 'अच्छे हैप्पीनेस इंडेक्सह्न वाले देशों में, अपने बच्चों के कॅरियर के चुनाव में माता-पिता की भूमिका आम तौर पर निर्णय को थोपने या नियंत्रित करने के बजाय समर्थन और मार्गदर्शन की होती है। माता-पिता अपने बच्चे की व्यक्तिगत रुचियों, कौशल और शौक को प्राथमिकता देते हैं, उन्हें अलग-अलग विकल्पों का पता लगाने और ऐसे विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो व्यक्तिगत संतुष्टि और खुशी की ओर ले जाते हैं।

जबकि भारतीय पैरेंट्स बच्चों की रुचि से अलग पड़ोसी एवं रिश्तेदारों के बच्चों से तुलना करके या कुछेक कॅरियर विकल्प अपनाने का दबाव बनाते है। इच्छा विपरीत थोपे गये विकल्प निराशा की भावना पैदा करते हैं।एनसीआरबी के अनुसार, 2024 में देश में लगभग 14488 छात्रों की आत्महत्या से मृत्यु हो गई। महाराष्ट्र में सबसे अधिक आत्महत्याएं दर्ज की गईं। राजस्थान में भी ये आंकड़े लगातार बढ रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से ऐसे मामलों को लेकर कोचिंग संचालकों, अभिभावकों, प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकें की जा रही हैं। बच्चों में आत्महत्या के बढते मामलों में हम सिर्फ कोचिंग संस्थानों पर दोषारोपण करके स्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते। वास्तव में इन चीजों को ठीक करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में नजरिए को बदलने की जरूरत है। मैंने परामर्श सेवाओं के दौरान ऐसे काफी बच्चे देखें है, जो मानसिक स्वास्थ्य समस्या का सामना तो कर ही रहे होते हैं पर इस बात को लेकर भी परेशान हो रहे होते हैं कि यह समस्या घरवालों को पता ना लगे वरना वो इसे मेरी व्यक्तिगत कमजोरी या पढ़ाई लिखाई ना करने की मेरी नियत की तरह देखेंगे।मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा एक आम भ्रम है कि छोटी उम्र में मानसिक समस्या नहीं हो सकती है, जबकि यह एक गलत धारणा है। दरअसल, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं किसी को भी, किसी भी उम्र में हो सकती हैं। हालांकि बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बड़ों की तुलना में कम होती हैं। विद्यार्थी वर्ग में बढ़ती ऑनलाइन मोबाइल गेमिंग की लत, आक्रामकता, नशे की प्रवृत्ति एवं इनसे संबधित बाल अपराधों के बढ़ते आंकड़े स्थिति की गंभीरता की तरफ इशारा कर रहे हैं। ओटीटी पर परोसी जाने वाली हिंसक सामग्री एवं गाली गलौज का अत्यधिक प्रभाव विकसित होते बालमन पर बहुत नकारात्मक होता है। सोशल मीडिया पर दूसरों से तुलना करने की प्रवृत्ति बढ़ती है जिससे कमतरी की भावनाएं पैदा होती हैं इससे असंतोष और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। साइबर बुलिंग से भी मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के तुलनात्मक अध्ययनों के अनुसार भारत में छात्र पहले की तुलना में अधिक तनावग्रस्त हैं। बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। आइसीएमआर की एक रिपोर्ट के अनुसार 4 से 16 वर्ष की आयु के बीच 12 से 14 प्रतिशत भारतीय छात्र मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। और अब ये आंकड़े और बढ रहे हैं। इंडियन साइकियाट्रिक सोसायटी के एक अध्ययन एवं मानव संसाधन मंत्रालय के बताये आंकड़ों के अनुसार, इन सालों में देश में मानसिक रोगों से पीड़ित मरीजों की संख्या 15 से 20 फीसदी तक बढ़ गई है। विद्यार्थी वर्ग भी इससे अछूता नहीं है। कोचिंग करने वाले बच्चों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में स्कूल मेंटल हैल्थ (एसएमएच) जैसे कार्यक्रम उपयोगी साबित हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डबल्यू एच ओ) ने एसएमएच को स्कूलों में आवश्यक रूप से लागू करने की सिफारिश की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएससी) ने बच्चों में तनाव को कम करने और स्कूलों में कार्यक्रमों के माध्यम से सकारात्मक रवैया अपनाने पर जोर दिया है। पर अब भी इस दिशा में किए गए प्रयास काफी कम हैं। सीबीएससी का सुझाव है कि सभी माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में एक काउंसलर नियुक्त करना चाहिए, जिससे छात्रों का आत्मविश्वास, विपरीत परिस्थितियों या दबावों को झेलने की क्षमता और सीखने की क्षमता को बेहतर किया जा सके। विद्यार्थियों को मानसिक तौर पर स्वस्थ रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह संख्या देश की हेल्थ इकोनॉमी की सूचक है। इससे न केवल परिवार एवं समाज पर बल्कि पूरे देश के विकास पर असर पड़ता है। इसीलिए बढ़ती किशोर मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं एसएमएच कार्यक्रमों की आवश्यकता को बताती हैं।

बदलते वैश्विक समीकरणों में नई दिशा की उम्मीद

भारत नहीं चाहता कि ब्रिक्स धीरे-धीरे चीन की आर्थिक शक्ति और रूस की पश्चिम-विरोधी राजनीति का तंत्र बन जाए। इसलिए शायद भारतीय रणनीति संतुलन की कला है। चीन के साथ सहयोग, लेकिन चीन-केंद्रितता नहीं, रूस के साथ संवाद लेकिन रूस-केंद्रित एजेंडा नहीं, ग्लोबल साउथ का नेतृत्व, लेकिन उसके नाम पर वर्चस्व का दावा नहीं। भारत के सामने अवसर है कि वह विस्तारित ब्रिक्स में बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा के बीच मध्यम और छोटे देशों को भी जगह दिला सके। यही भारत की अध्यक्षता की उपलब्धि होगी।

स्वर्ण सिंह

कभी-कभी किसी शिखर सम्मेलन की अहमियत उसके एजेंडे से कम और उस मोड़ से अधिक तय होती है जिस पर वह आयोजित हो रहा होता है। नई दिल्ली में इस सप्ताह होने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कुछ ऐसे ही मोड़ पर है। दुनिया एक साथ कई संक्रमणों से गुजर रही है- शक्ति का पश्चिम से पूर्व की ओर सरकना, वैश्वीकरण का विखंडन, युद्धों की वापसी, आपूर्ति-शृंखलाओं की असुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की ऐसी छलांग कि इसके नियम अभी लिखे ही जा रहे हैं। इसी उथल-पुथल के बीच भारत एक साल से ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि ब्रिक्स के दिल्ली घोषणापत्र में किस भाषा पर सर्वसम्मति कैसे बनेगी, बड़ा सवाल यह है कि ब्रिक्स के परिवर्तनशील लंबे सफर में भारत की इस अध्यक्षता की क्या अमिट छाप बनेगी।

सबसे पहले तो ब्रिक्स अब वह सीमित क्लब नहीं रहा जिसकी कल्पना मूलतः इस शताब्दी की शुरूआत में ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने की थी। ब्रिक्स के विस्तार ने उसके भूगोल और आर्थिक वजन के साथ-साथ अंतर्विरोध को भी बढ़ा दिया है। इसमें ऐसी अर्थव्यवस्थाएं और राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, जिनकी प्राथमिकताएं एक-दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खातीं। एक ओर चीन और रूस हैं, जो पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देने की मुखर आकांक्षा रखते हैं। दूसरी ओर भारत है, जो बहुध्रुवीयता चाहता है और अपने को किसी एक खेमे में आत्मसात नहीं करना चाहता। यहीं से दिल्ली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अग्निपरीक्षा शुरू हो जाती है।

भारत ने लगातार ब्रिक्स को 'पश्चिम के विरुद्ध' मंच बनाने के बजाय 'ग्लोबल साउथ के लिए मंच' बनाने की प्रस्तावना की है। भारत के लिए ब्रिक्स की उपयोगिता तभी बढ़ सकती है जब वह विकासशील देशों की उन समस्याओं पर कुछ कर सके जो उनकी रोजमर्रा की आर्थिक असुरक्षा से जुड़ी है- ऊर्जा, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, वित्त, तकनीकी असमानता और अस्थिर आपूर्ति-शृंखलाएं। इसलिए भारत की अध्यक्षता का घोषित मंत्र- लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता- दरअसल ब्रिक्स को भू-राजनीतिक घोषणाओं से कहीं आगे ले जाने का प्रयास है। इस मंत्र में भारत की अपनी विदेश नीति का मौलिक सूत्र-'रणनीतिक स्वायत्तता, लेकिन रणनीतिक अलगाव नहीं'- भी साफ दिखाई देता है। भारत अमरीका और सभी दूसरे साथी देशों के साथ साझेदारी करता है पर रूस से भी प्रगाढ़ संबंध बनाए रखता है, चीन के साथ प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों करता है। ऐसा करके भारत ब्रिक्स को किसी नए शीतयुद्ध का औजार नहीं बनने से बचाना चाहता है। इसलिए भारत की ग्लोबल साउथ में स्वीकार्यता लगातार भी बढ़ी है।

पर भारत के इस सबसे मेलजोल रखने का यह अर्थ नहीं कि भारत वैश्विक शासन-व्यवस्था में बदलाव नहीं चाहता। उल्टे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से लेकर वैश्विक वित्तीय संस्थाओं तक अधिक प्रतिनिधित्व और अधिक न्यायपूर्ण व्यवस्था की उसकी मांग ब्रिक्स के राजनीतिक एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। भारत का तर्क यह है कि बहुध्रुवीय दुनिया का अर्थ एक पश्चिमी प्रभुत्व की जगह किसी दूसरे प्रभुत्व को स्थापित करना नहीं, बल्कि अधिक सामरिक विकल्प पैदा करना है। यही वह बिंदु है, जहां भारतीय ब्रिक्स दृष्टि, चीनी या रूसी दृष्टि से अलग दिखाई देती है। भारत की दूसरी बड़ी कोशिश ब्रिक्स को ऐसी संस्था बनाना है, जो केवल घोषणाएं न करे, बल्कि काम करने वाले तंत्र भी बनाए। यही कारण है कि उसकी इस साल की ब्रिक्स अध्यक्षता में आपूर्ति शृंखलाएं डिजिटल भुगतान, स्थानीय मुद्राएं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, न्वोद्यम और हरित ऊर्जा जैसे अपेक्षाकृत व्यावहारिक मुद्दे प्रमुख रहे हैं। यह सब ब्रिक्स को समावेशन और विकास का सार्वजनिक मंच बनाने में सहायक हो सकते है।

इसी तरह वित्तीय सहयोग में भी भारत की चुनौतियां दिलचस्प है। ब्रिक्स के भीतर राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार और सीमा-पार भुगतान प्रणालियों को जोड़ने की चर्चा होती रही है। लेकिन भारत ने किसी 'ब्रिक्स मुद्रा' को जल्दबाजी में बाजार में उतारने को अपनी प्राथमिकता नहीं बनाया है। वह अधिक व्यावहारिक, स्थानीय मुद्राओं में भुगतान को पहले लागू करने पर जोर देता है। यूपीआइ का अनुभव भारत ब्रिक्स के मंच से ग्लोबल साउथ के सामने रख सकता है। आने वाले वर्षों में असली शक्ति केवल इसमें नहीं होगी कि तकनीक किसके पास है, बल्कि इस बात से भी कि इसके नियम कौन लिखता है, डेटा किसके पास है और विकासशील देशों को उपभोक्ता के बजाय भागीदार कौन बनाता है। दिल्ली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की कहानी जितनी आशावादी है, उतनी सरल नहीं है। ब्रिक्स के विस्तार ने उसकी शक्ति को बढ़ाया हैं मगर सर्वसम्मति बनाना कठिन कर दिया है। पश्चिम एशिया, यूक्रेन, अमरीकी प्रतिबंधों और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सदस्य देशों के हित और दृष्टिकोण अलग-अलग हैं। मई में नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में संयुक्त घोषणा-पत्र बैठक के अध्यक्ष के व्यक्तव्य तक सीमित रह जाना इस कठिनाई का संकेत था। चीन इस समूह की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसके बिना ब्रिक्स की आर्थिक क्षमता की कल्पना अधूरी होगी। लेकिन भारत नहीं चाहता कि ब्रिक्स धीरे-धीरे चीन की आर्थिक शक्ति और रूस की पश्चिम-विरोधी राजनीति का तंत्र बन जाए। इसलिए शायद भारतीय रणनीति संतुलन की कला है। चीन के साथ सहयोग, लेकिन चीन-केंद्रितता नहीं, रूस के साथ संवाद लेकिन रूस-केंद्रित एजेंडा नहीं, ग्लोबल साउथ का नेतृत्व, लेकिन उसके नाम पर वर्चस्व का दावा नहीं। भारत के सामने अवसर है कि वह विस्तारित ब्रिक्स में बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा के बीच मध्यम और छोटे देशों को भी जगह दिला सके। यही भारत की अध्यक्षता की उपलब्धि होगी।

भारत ब्रिक्स को पश्चिम का विकल्प बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। वह उसे विकल्पों की दुनिया का मंच बनाने की कोशिश कर रहा है। यह अंतर उसकी पूरी कूटनीतिक दृष्टि को समझने की कुंजी है। ग्लोबल साउथ को आज किसी नए खेमे की नहीं, विकल्पों की जरूरत है। यदि भारत इस गुंजाइश को संस्थागत रूप दे पाता है, तो ब्रिक्स की अगली कहानी शायद यह नहीं होगी कि कौन दुनिया का नेतृत्व करेगा। असली कहानी यह होगी कि दुनिया को कितने विकल्प संभव और सुदृढ़ हैं। भारत की कोशिश यही है कि उन विकल्पों में भारत की आवाज स्पष्ट सुनाई दे और ग्लोबल साउथ की आवाज केवल सुनी ही नहीं जाए, बल्कि प्रभावशाली भी बने।

जीवन को बेहतर समझना

श्रीश्री रवि शंकर

चिंतन-मनन

यदि आपसे पूछा जाए कि आपको जीवन में क्या चाहिए तो आप यही कहेंगे कि आपको सुख और शांति चाहिए। लोग धन के पीछे भी इसीलिए भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे उससे सुखी रह पाएंगे और उससे उनके जीवन में शांति रहेगी। लेकिन यदि धन सुख-शांति न देकर गले की फांसी बन जाए, तब भी उसे पकड़ कर रखना बेवकूफी है। इसीलिए हमें जीवन का सत्य समझना आवश्यक है। हमें यह जानना आवश्यक है कि जीवन में नित्य क्या है और अनित्य क्या है? यदि जीवन को इसकी पूर्णता में समझना हो तो आपको कुछ विशेष अनुभव प्राप्त करने चाहिए, कम से कम एक दिन किसानों के साथ, एक दिन स्कूल में, एक दिन पागलखाने में, एक दिन जेल में और एक दिन अस्पताल में बिताना चाहिए। इन पांच दिनों में ही आपकी समझ बहुत विकसित हो जाएगी और आपका पूरा व्यक्तित्व खिल जाएगा। किसी गांव में जब कोई किसान खेत में बीज बो रहा हो या फसल काट रहा हो तब दिन भर उसके साथ रहिए। आप देखेंगे कि किसान सबका पेट भरने के लिए दिन-रात कितनी परिश्रम करता है। इससे आपके हृदय में किसान के प्रति प्रेम और स्नेह जगेगा, प्रकृति के प्रति आपकी कृतज्ञता बढ़ेगी और पर्यावरण के प्रति आप और अधिक संवेदनशील हो जाएंगे। एक दिन स्कूल में आधा दिन बच्चों के साथ बच्चे बन कर रहिए और आधा दिन शिक्षक बनकर। जब तक आप किसी के गुरु नहीं बनेंगे तब तक आपके भीतर स्नेह, ममता और करुणा नहीं जाग्रत होगी, क्योंकि गुरु के प्रेम में कोई प्रतिबंध नहीं होता। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि शिष्यात् इच्छेत् पराजयम माने हर गुरु यही चाहते हैं कि मेरे शिष्य से ही मेरी पराजय हो और किसी से नहीं अर्थशास्त्र, राजनीति, कला या अध्ययन किसी भी क्षेत्र में हर गुरु की यही इच्छा होनी चाहिए कि उनके शिष्य उनसे आगे बढ़ें और जो विद्या उन्होंने प्राप्त की वह और अधिक लोगों तक पहुंचे। जब आप स्कूल के शिक्षक बन कर काम करेंगे तब आपको यह भी पता चलेगा कि बच्चों का पालन कैसे करना चाहिए। कई बार जब हम व्यस्त होते हैं तो बच्चों को डे केयर होम में छोड़ देते हैं और वहां उनके शिक्षक उनसे जूझते रहते हैं। इसलिए बच्चों के व्यवहार में सुधार कैसे लाना है यह समझने के लिए आपको एक दिन शिक्षक बन कर देखना चाहिए। इसी तरह से एक दिन पागलखाने जाकर देखिए।

आपके पत्र

मिट्टी बचेगी, तभी खेती बचेगी

भारतीय कृषि अब एक नए युग की ओर अग्रसर है, जहां विकास का आकलन करने के लिए केवल वृद्धि ही एकमात्र मापदंड नहीं रह गया है। मिट्टी की घटती उर्वरता, भूजल की कमी, जैव विविधता का क्षय, जलवायु परिवर्तनशीलता और बढ़ती खेती लागत के कारण किसान और कृषि क्षेत्र पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। इस संदर्भ में पुनर्योजी कृषि एक आशाजनक मार्ग है। यह एक समग्र दृष्टिकोण है जो न केवल वर्तमान प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेगा, बल्कि वास्तव में मिट्टी के स्वास्थ्य, जैव विविधता, जल प्रणालियों और पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों को बेहतर बनाकर कृषि उत्पादकता को बनाए रखेगा। मुख्य बात पुनर्योजी कृषि पर ध्यान केंद्रित करना और कृषि के पारिस्थितिक स्तंभों को पुनर्स्थापित करना है। अगर मिट्टी बचेगी, तो ही खेती बचेगी। मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखना होगा।

पीके वर्मा,रांची

मेट्रो रेज की ओर से स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक जीतेन्द्र कुमार सिंह के लिए जेके न्यूज नेटवर्क, पिपरटोली, अरगोड़ा, रांची 834002 (झारखंड) से प्रकाशित तथा शिवासाईं पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नियर टेंडर बागीचा, पेट्रोल पंप रातू रोड, रांची , (झारखंड) से मुद्रित।
प्रधान संपादक : जीतेन्द्र कुमार सिंह, **संपादक** : लाल दिवाकर नाथ शाहदेव*, *पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार। समस्त दिवानी विवादों, न्यायोचित कार्रवाइयों एवं दंडित परिवादों के लिए क्षेत्राधिकार रांची न्यायालय में रहेगा। फोन : 7369017908, R.N.I. No.-JHAHIN/2017/75028 **website : www.metrorays.in**
email : metrorays.ranchi@gmail.com

बरहरवा से 1.20 करोड़ की साइबर ठगी मामले में पुलिस ने तीन को किया गिरफ्तार

संवाददाता

साहिबगंज : बीते दिनों साइबर ठगी की एक बड़ी वारदात की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी थी।जिसमें बरहरवा थाना क्षेत्र निवासी गौतम दास को डिजिटल एसरेस्ट कर उससे 1 करोड़ 20 लाख की साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया था,जिस मामले में पुलिस पूरी सक्रियता से पड़ताल में जुट गई था,जिसके फलस्वरूप पुलिस ने उद्भेदन करते हुए 03 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।पुलिस लाइन स्थित एसपी कार्यालय सभागार में बुधवार को डीएसपी रविकांत साव ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि अज्ञात साइबर अपराधियों ने गौतम दास को वाट्सअप कॉल कर स्वयं को सीबीआई बताते हुए मानसिक भय दिखाया था।अपराधियों ने वादी को अश्लील वीडियो एवं उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होने का झूठा डर दिखा कर वादी से एक करोड़ बीस लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरित करवा लिया था।इस सम्बंध में 31 अगस्त 2026 को बरहरवा थाना में कांड संख्या 218/26 दर्ज किया गया था।कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने डीएसपी सह साइबर सेल नोडल पदाधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था एसआईटी ने बैंक स्टेटमेंट एवं तकनीकी शाखा के सहयोग से कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल के दुगार्पुर क्षेत्र के रहने वाले अंतर राज्य संगठित साइबर गिरोह के तीन अपराधियों को धर दबोचा।गिरफ्तार आरोपियों में पश्चिम बंगाल वर्द्धमान, दुगार्पुर,बॉम्बे कॉलोनी निवासी रंजीत बास्की एनटीपीसी विद्यानगर आईटीआई,गोसाईं टोला निवासी आसित महतो एवं विधाननगर हुरको दुगार्पुर निवासी धीरज हारी शामिल है।डीएसपी ने बताया कि इस पूरी वारदात को अंजाम देने में 7-8 लोग शामिल थे पश्चिम बंगाल,दिल्ली,यूपी व हैदराबाद से गिरोह ऑपरेट हो रहा था। तीनों को दुगार्पुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है।अभी तक इस मामले में 31 लाख रुपये की बरामदगी की जा चुकी है।पूरी रकम की ठगी में 4 हजार अकाउंट का इस्तेमाल किया गया। जबकि 5500 बार ट्रांजेक्शन किये गए।वारदात में शामिल अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।छापामारी दल में बरहरवा पुलिस निरीक्षक संतोष कुमार,पुलिस अवर निरीक्षक अनिल कुमार,पुलिस अवर निरीक्षक सत्यवान कुंभकार व अन्य शामिल थे।

न्यूज IN ब्रीफ

बाबूलाल मरांडी पहुंचे साहिबगंज भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत

साहिबगंज : प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बुधवार शाम को सड़क मार्ग से साहिबगंज पहुंचे। पाकुड़ के रास्ते बरहरवा,पतना, बरहेट,बोरियो,बांझी व साहिबगंज पहुंचने पर उक्त क्षेत्र के कार्यकताओं ने फूल माला पहनाकर बुके व अंग वस्त्र देकर स्वागत किया।वही साहिबगंज सर्किट हाउस पहुंचने पर पूर्व विधायक अनंत ओझा,प्रेमलाल मंडल उर्फ मंटा मंडल,प्रदेश कार्यसमिति सदस्य गणेश तिवारी व रामानंद साह ओर धर्मेंद्र कुमार सहित भाजपा कार्यकताओं ने स्वागत किया।वही आज होने वाली डीसी एसपी घेराव को लेकर भाजपा अधिकारियों के साथ बैठक करके विचार विमर्श किया।मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष गौतम यादव सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।

बाढ़ प्रभावितों के बीच आजसू ने बांटी राहत सामग्री, कोई भूखा न रहे : चतुरानंद पांडेय

साहिबगंज : जिले में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। गांव से लेकर दियारा क्षेत्र और शहरी इलाकों तक बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। कई बाढ़ प्रभावित परिवार अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों, सड़क किनारे और गंगा तट के आसपास रहने को मजबूर हैं।बाढ़ प्रभावित लोगों की स्थिति को देखते हुए आजसू पार्टी की ओर से राहत अभियान चलाया गया। जिला अध्यक्ष चतुरानंद पांडेय के नेतृत्व में कार्यकताओं ने बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच पहुंचकर राहत सामग्री का वितरण किया। इस दौरान प्रभावित परिवारों के बीच चूड़ा, गुड़, मोमबत्ती, दालमोट, माचिस सहित अन्य आवश्यक खाद्य एवं उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराई गई।जिला अध्यक्ष चतुरानंद पांडेय ने कहा कि गंगा के बढ़ते जलस्तर ने दियारा क्षेत्र के कई गांवों को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया है। बाढ़ का पानी घरों में प्रवेश करने से बड़ी संख्या में ग्रामीण अपने घरों से बाहर रहने को विवश हैं। कई परिवार गंगा किनारे और अन्य सुरक्षित स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि कोई भी प्रभावित परिवार भूखा न सोए।उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी के कार्यकर्ता बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार लोगों के संपर्क में हैं और जरूरतमंद परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बाढ़ की स्थिति सामान्य होने तक प्रभावित लोगों की हरसंभव मदद के लिए कार्यकर्ता सक्रिय रहेंगे।राहत वितरण के दौरान आजसू पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने प्रभावित लोगों की समस्याएं भी सुनीं। पार्टी की ओर से जरूरत के अनुसार आगे भी राहत सामग्री उपलब्ध कराने की बात कही गई।

कोयला ढुलाई की याचिका को एनजीटी ने किया खारिज

बड़कागांव : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), कोलकाता पीठ ने पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना से सड़क मार्ग के जरिए कोयला परिवहन को लेकर दायर शिकायत को खारिज कर दिया है। याचिका में दावा किया गया था कि परियोजना से कोयले का परिवहन सड़क मार्ग से निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करते हुए किया जा रहा है। शिकायत पर सुनवाई के बाद एनजीटी ने स्पष्ट किया कि परियोजना को 30 सितंबर 2026 तक सड़क मार्ग से कोयला परिवहन की अनुमति प्राप्त है। ऐसे में परियोजना की ओर से इस संबंध में किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है। अधिकरण ने यह भी माना कि सड़क मार्ग से किया जा रहा कोयला परिवहन परियोजना पर लागू वन स्वीकृति का उल्लंघन नहीं है।

निशुल्क दंत चिकित्सा शिविर में 542 मरीजों का पंजीकरण

हजारीबाग : कृष्णापुरी, मटवारी स्थित परफेक्ट स्माइल डेंटल क्लीनिक में 8 और 9 सितंबर को आयोजित निशुल्क दंत चिकित्सा शिविर के लिए 542 मरीजों ने पंजीकरण कराया। रजिस्ट्रेशन के दौरान लोगों में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों सहित सभी आयु वर्ग के लोगों ने शिविर का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराया। भारी भीड़ को देखते हुए डॉ आशीष श्रीवास्तव ने रजिस्ट्रेशन की पर्याप्त व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि समाज की सेवा और लोगों को बेहतर दंत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना शिविर का मुख्य उद्देश्य है।10 से 12 सितंबर तक चलने वाले इस निशुल्क शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा दंत जांच एवं उपचार किया जाएगा। शिविर में नॉन-सर्जिकल एक्सट्रैक्शन, दांतों की सफाई, डेंटल चेकअप, एक्स-रे और निशुल्क दवा वितरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। लोगों की भागीदारी से दंत स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ने की उम्मीद है।

मंत्री सुदिव्य सोनू के आकस्मिक निधन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जताया शोक

विष्णुगढ़ : विष्णुगढ़ प्रखंड कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को राज्य के कबीना मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के निधन पर गहरा शोक जताया है। इसके लिए विष्णुगढ़ झारखंड कार्यालय में कांग्रेस कार्यकताओं ने दो मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। प्रखंड अध्यक्ष गुरु प्रसाद साव ने कहा कि जिला अध्यक्ष के निदेर्शानुसार अगले आदेश तक पार्टी के सभी आंदोलनात्मक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। प्रखंड अध्यक्ष गुरु प्रसाद साव ने कहा कि सुदिव्य कुमार सोनू काफी व्यवहारिक और मिलनसार नेता थे।अपनी सादगी के कारण वे एक सामान्य कार्यकर्ता से राजनीतिक जीवन की शुरूआत कर मंत्री पद तक पहुंचे। झारखंड आंदोलन में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। झारखंड आंदोलनकारी गिरिडीह के पूर्व सांसद स्व. टेकलाल महतो के साथ भी उन्होंने काम किया था। श्रद्धांजलि सभा में नेपाल में हुई त्रासदी तथा दिल्ली के पीजी हॉस्टल गिरने से हुई मौतों पर भी शोक जताते हुए श्रद्धांजलि दी गई। पीजी हॉस्टल के मृतक के परिजनों को नौकरी तथा घायलों के समुचित इलाज की मांग की गई। मौके पर सुरेंद्र मिश्रा, अब्बास अंसारी, तारकेश्वर महतो, विशेश्वर स्वर्णकार, नारायण महतो उपस्थित थे।

मतदाता सूची के एसआईआर कार्य का निरीक्षण निवार्ची पदाधिकारी ने किया

संवाददाता

साहिबगंज : मतदाता सूची को त्रुटिरहित, अद्यतन एवं अधिक समावेशी बनाने के उद्देश्य से जिले में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य का सतत अनुश्रवण और क्षेत्रीय निरीक्षण किया जा रहा है।इसी क्रम में निवार्ची पदाधिकारी 2 बोरियो विधानसभा सह-अनुमंडल पदाधिकारी साहिबगंज अमर जॉन आईन्द द्वारा बोरियो विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बोआरीजोर प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्रों का भ्रमण कर विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित कार्यों का स्थल निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित बीएलओ एवं निर्वाचन कर्मियों से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की प्रगति की जानकारी ली तथा प्रपत्रों के संधारण मतदाताओं से प्राप्त आवेदनों व आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन सहित विभिन्न बिंदुओं की गहन समीक्षा की।निवार्ची पदाधिकारी ने सभी संबंधित कर्मियों को निर्देशित किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य पूरी पारदर्शिता निष्पक्षता एवं निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए। पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल करने तथा अपात्र, मृत अथवा स्थानांतरित मतदाताओं से संबंधित मामलों का नियमानुसार सत्यापन करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया।उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती के लिए शुद्ध व अद्यतन मतदाता सूची अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए पुनरीक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए आम नागरिकों को आवश्यक सहयोग एवं जानकारी उपलब्ध कराते हुए उनके दावों एवं आपत्तियों का नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

कीटनाशी विक्रेताओं को दिया गया एक दिवसीय प्रशिक्षण

संवाददाता

साहिबगंज : जिला कृषि विभाग की ओर से फसल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत कीटनाशी दवा विक्रेताओं के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बुधवार को आत्मा सभागार में आयोजित किया गया।प्रशिक्षण का उद्देश्य किसानों को कीटनाशकों के सुरक्षित एवं उचित उपयोग की जानकारी उपलब्ध कराना और फसल सुरक्षा को बेहतर बनाना रहा।कार्यक्रम में जिला कृषि पदाधिकारी वरुण कुमार ने कीटनाशी विक्रेताओं को निर्देश देते हुए कहा कि प्रतिबंधित कीटनाशक दवाओं की बिक्री किसी भी परिस्थिति में नहीं की जाए।साथ ही सरकार एवं कृषि विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरश पालन करने की बात कही।उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान दी जा रही जानकारी को गंभीरता से समझें और किसानों तक सही जानकारी पहुंचाएं,ताकि जिले के किसानों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके।कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉ।संजीव कुमार ने कीटनाशी दवाओं के सही मात्रा में प्रयोग की जानकारी दी।उन्होंने बताया कि किसी भी कीटनाशी दवा के छिड़काव से पहले खेत के क्षेत्रफल की सही जानकारी होना आवश्यक है।क्षेत्रफल के आधार पर ही दवा की निर्धारित मात्रा तय कर छिड़काव किया जाना चाहिए,ताकि फसल को नुकसान न पहुंचे और दवा का प्रभावी उपयोग हो सके।वहीं आत्मा के मंटू कुमार ने फसलों में तना छेदक जैसे कीटों से होने वाले नुकसान और उनकी रोकथाम के उपायों पर विस्तार से जानकारी दी।बरहेट क्षेत्र से आए राजदेव ने फसल के लिए लाभकारी मित्र कीटों की पहचान करने के तरीकों पर चर्चा की तथा किसानों को मित्र एवं हानिकारक कीटों के बीच अंतर समझाने की जानकारी दी।प्रशिक्षण कार्यक्रम में साहिबगंज जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में कीटनाशी दवा विक्रेताओं ने भाग लिया।प्रशिक्षण के दौरान फसल सुरक्षा,कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग एवं किसानों को उचित सलाह देने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गईं।

पाकुड़ में भाजपाईयों ने किया समाहरणालय का घेराव

भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच और छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग

पाकुड़: झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में धांधली और भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच और आंदोलनकारी छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकताओं ने पाकुड़ समाहरणालय का घेराव किया। इस दौरान भाजपा कार्यकताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की ।

बाबूलाल ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना

पाकुड़ समाहरणालय घेराव का नेतृत्व झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया। उन्होंने वर्तमान राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत शासनकाल में पैसे लेकर नौकरी बेचने का काम किया गया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में भर्ती घोटाले की जांच सरकार ने वैसे अधिकारी को सौंपी है जो खुद विवादों से घिरे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आंदोलन को दबाने के लिए हेमंत सरकार ने तानाशाही और दमनकारी नीति अपनाकर निर्दोष छात्रों पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया।

उन्होंने कहा कि झारखंड में भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से नहीं कराई गई और छात्रों पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो आने वाले दिनों में डीसी कार्यालय में घुसने का काम किया जाएगा। समाहरणालय घेराव कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता दिनेश विलियम मरांडी, जिलाध्यक्ष सरिता मुर्मू सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए।

मौके पर प्रदेश प्रवक्ता दिनेश विलियम मरांडी, प्रदेश मंत्री कृष्णा महतो, पाकुड़ प्रभारी निवास मंडल, जिलाध्यक्ष सरिता मुर्मू, अल्पसंख्यक मोर्चा की पूर्व राष्ट्रीय मंत्री मिस्फीका हसन, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य दुर्गा मरांडी, पूर्व जिलाध्यक्ष अमृत पांडेय, विवेकानंद तिवारी, मीरा प्रवीण सिंह, जिला महामंत्री रुपेश कुमार भगत ने भी संबोधित किया।

जेएसएलपीएस कैडरों ने मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को सौंपा सात सूत्री मांग पत्र

संवाददाता

बड़कागांव : जेएसएलपीएस में कार्यरत कैडरों का मानदेय सम्मानजनक वृद्धि एवं यात्रा भत्ता सहित सात सूत्री मांग को लेकर सभी कर्मियों ने मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार के नाम उपायुक्त के माध्यम से मांग पत्र सौंपा गया। सौंपे गए मांग पत्र में कहा है कि जेएसएलपीएस के साथ कार्यरत विभिन्न इकाई के कैडर जीसीआरपी, बीडीएसपी, सीआरपी, ईपी, सेतु दीदी, एफएलसीआरपी, एडब्ल्यू, एकेएम, एपीएस, जेआरपी एवं ईबीके सहित कई इकाई के कैडर वर्षों से ग्रामीण समुदाय के बीच आजीविका संवर्धन, वित्तीय समावेश, उद्यमिता विकास, सामुदायिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण तथा जेएसएलपीएस की विभिन्न गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कैडरों के द्वारा निर्धारित दायित्व के साथ-साथ आवश्यकता के अनुसार क्षेत्रीय भ्रमण, बैठक, प्रशिक्षण, सामुदायिक संस्थाओं के साथ अन्य अधिकृत कार्य भी किए जाते हैं।

कार्य की प्रकृति, जिम्मेवारी, समय तथा क्षेत्रीय आवागमन में होने वाले व्यय की तुलना में वर्तमान मानदेय सभी कैडरों का अपर्याप्त है। साथ ही मानदेय में समयानुकूल एवं सम्मानजनक वृद्धि किया जाना आवश्यक है।

रिसोड पंचायत ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हुए डॉ तनवीर

संवाददाता

साहिबगंज/बरहरवा : झारखंड प्रदेश कांग्रेस महासचिव डॉ तनवीर आलम ने बुधवार को बरहरवा प्रखंड अंतर्गत रिसोड पंचायत के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने चाँदपुर, चंदनपुर व मेहंदीडांग गांव पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं एवं क्षेत्र की आवश्यकताओं की जानकारी ली।क्षेत्र भ्रमण के दौरान चाँदपुर गांव में ओबैदुर के घर के पास चंदनपुर गांव में बरकत के घर के पास तथा मेहंदीडांग गांव में स्कूल के समीप ग्रामीणों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।बैठक के दौरान स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एस आईआर से संबंधित कार्यों को लेकर भी ग्रामीणों के बीच व्याप्त आशंकाओं एवं सवालों पर डॉ। तनवीर आलम ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि एसआईआर को लेकर किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को नोटिस प्राप्त होता है।तो सबसे पहले यह जानकारी लें कि नोटिस किस कारण से जारी किया गया है। इसके बाद संबंधित कारण के अनुसार आवश्यक दस्तावेज तैयार कर निर्धारित तिथि पर प्रखंड कार्यालय पहुंचें।उन्होंने कहा कि यदि किसी कारणवश प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में कोई कमी रह जाती है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति को अगली तारीख दी जाएगी और आवश्यक दस्तावेजों को पूरा करने का अवसर मिलेगा।इसके अलावा ग्रामीणों ने पानी, सड़क, नाला, मंईयां सम्मान योजना सहित कई जनसमस्याओं को डॉ। तनवीर आलम के समक्ष रखा। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए कहा कि जनहित से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा। संबंधित विभागों के अधिकारियों के समक्ष समस्याओं को प्रमुखता से रखा जाएगा, ताकि ग्रामीणों को जल्द राहत मिल सके।क्षेत्र भ्रमण के दौरान जिला अध्यक्ष सह विधायक प्रतिनिधि बरकत खान प्रखंड अध्यक्ष रंजीत टुडू, प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष अशोक कुमार दास,नेहाल अख्तर, शारिक रब्बानी ओबैदुर रहमान,फिरोज आलम,हाजी अलाउद्दीन,मुन्ना पांडे,फैजुल रहमान, रबीउल शराफत बरकत,सनाउल, दुलाल, अब्दुल रशीदमुख्तार,जहांगीर सहित स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता व बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

लिफ्ट करा दे को रिलीज करने से डर रहा था रिकॉर्ड लेबल, अदनान सामी ने सुनाया दिलचस्प किस्सा,

कोमल नाहटा देश के सबसे जाने-माने ट्रेड एनालिस्ट में से एक हैं। जिन्होंने अपने पॉपुलर पॉडकास्ट गेम चेंजर्सः द म्यूज़िक सीरीज के नए सीजन के साथ फिर से वापसी की है। इस नए सीजन में कई जाने माने सिंगर्स, कंपोजर्स और म्यूज़िक मास्टर्स ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और कितने ही दिलचस्प किस्से और बाते साझा की हैं। उनके द्वारा साझा की गई बातों ने न सिर्फ उत्सुकता को बढ़ाया है बल्कि उनके क्रिएटिव सफर, गानों के पीछे छुपी अनकही कहानी से भी रूबरू कराया है। ऐसे ने इस एडिशन के लेटेस्ट एपिसोड में अदनान सामी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई।

भारत के सबसे सम्मानित पद्म श्री पाने वाले सिंगर अदनान सामी देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भी बड़ी फैन फॉलोइंग एंजॉय करते हैं। उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ सिंगर ही नहीं पियानिस्ट और कंपोजर के तौर पर भी जाना जाता है, जो अपनी जबरदस्त वोकल रेंज और इंडियन क्लासिकल और वेस्टर्न पॉप म्यूज़िक के सिग्नेचर मिक्स के लिए एक अलग पहचान रखते हैं। ऐसे में, सिंगर ने शो पर अपने लिए इंडस्ट्री में गेम चेंजर साबित होने वाले गाने के बारे में बात की है, साथ ही बताया है कि कैसे उनके सबसे बड़े हिट्स में से एक लिफ्ट करा दे लगभग नहीं बनने वाला था।

अदनान सामी कहते हैं, लिफ्ट करा दे वो गाना था, जिसने मुझे असल में लोगों के बीच पहचान दिलाई। मेरा गाना हर जगह एंथम की तरह बज रहा था। मजेदार बात ये है कि उस समय रिकॉर्ड लेबल इस गाने को रिलीज करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें इस गाने पर भरोसा नहीं था। उनका कहना था कि हमारे पास पहले से दो रोमांटिक गाने हैं और तीसरे गाने की बात आई तो वे एक और रोमांटिक गाना रखने के तरफ थे। मैंन लिफ्ट करा दे चुना और उसपर उन्होंने कहा, कहां बरसात और कहां कभी तो नजर मिलाओ और उनके सामने ये गाना कितना डाउनमार्केट है। रोमांटिक सिंगर के तौर पर आपकी इमेज बहुत सोफिस्टिकेटेड है।

अदनान सामी आगे कहा, मैंने कहा, मुझे इस गाने में पोटेंशियल दिख रहा है। मैं किसी एक जॉनर तक खुद को बांधे नहीं रखना चाहता। मैं हर तरह के गाने गाना चाहता हूं। यह वो समय है जब मैं उस सोच को तोड़ना चाहता हूं, ताकि लोग मुझे किसी एक खास तरह के सिंगर की कैटेगरी में न रखें। छह महीने तक लगातार मनाने के बाद उन्होंने मुझे यह गाना करने की इजाजत दी। पूरा गाना बिना किसी बजट के बनाया गया था; पूरी शूटिंग बॉम्बे की सड़कों पर सुबह-सुबह बिना किसी परमिशन के गुरिल्ला शूटिंग की तरह की गई थी। उन्हें कोई गारंटी नहीं थी कि यह गाना चलेगा, और अचानक यह बहुत बड़ा हिट हो गया। इसके बाद वे मेरे पास इसका रीमिक्स बनाने के लिए वापस आए।

कोमल नाहटा गेम चेंजर्स सीजनः द म्यूज़िक सीरीज के साथ भारतीय सिनेमा से जुड़ी बातचीत को फिर से परिभाषित कर रहे हैं। गेम चेंजरः द म्यूज़िक सीरीज को देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर ट्यून-इन करें।

जयपुर में 'आश्रम 4' की शूटिंग शुरू, होटल शिव विलास बना बाबा निराला का आलीशान दरबार

बॉबी देओल स्टारर चर्चित वेब सीरीज 'आश्रम' के चौथे सीजन की शूटिंग जयपुर में चल रही है। डायरेक्टर प्रकाश झा के निर्देशन में बन रही इस सीरीज का सेट जयपुर के कूकस स्थित होटल शिव विलास में तैयार किया गया है। यहां पिछले कई दिनों से सीरीज के अलग-अलग दृश्य फिल्माए जा रहे हैं। शूटिंग के लिए होटल परिसर को 'आश्रम' का रूप दिया गया है और सेट पर बाबा निराला के किरदार से जुड़ी बड़ी- बड़ी तस्वीरें भी लगाई गई हैं। साथ ही जयपुर के कलाकारों के ऑडिशन भी लिए जा रहे हैं।

आश्रम-4 का जयपुर में शूटिंग का एक लंबा शेड्यूल है। यहां सीरीज के कई महत्वपूर्ण दृश्य फिल्माए जाएंगे। फिलहाल सीरीज के कलाकार त्रिधा चौधरी और चंदन रॉय सान्याल सहित अन्य कलाकार शूटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। जल्द ही बॉबी देओल भी शूटिंग यूनिट से जुड़ सकते हैं। वहीं, ऑडिशन देने जयपुर पहुंचे कुछ कलाकारों ने शूटिंग लोकेशन के वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किए हैं। इनमें बताया गया है कि फिलहाल बॉबी देओल शूटिंग लोकेशन पर मौजूद नहीं हैं।

आश्रम का आलीशान सेटः शिव विलास होटल में तैयार किए गए सेट को बेहद भव्य और लग्जरी लुक दिया गया है। स्थानीय कलाकारों और शूटिंग से जुड़े लोगों ने सेट की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किए हैं। सेट पर आश्रम जैसा माहौल दिखाने के लिए विशेष सजावट की गई है। बाबा निराला के किरदार को प्रमुखता देने के लिए उनकी बड़ी तस्वीरें भी सेट पर लगाई गई हैं। शिव विलास से पहले जयपुर की जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी और मानसरोवर स्थित प्रियंका हॉस्पिटल में भी आश्रम के कुछ शॉट फिल्माए गए थे।

जयपुर के स्थानीय कलाकारों को भी मिला मौकाः आश्रम-4 की शूटिंग के लिए जयपुर और आसपास के इलाकों के बड़ी संख्या में स्थानीय कलाकारों के ऑडिशन लिए गए। इनमें से कई कलाकारों का चयन बाबा निराला के शिष्यों और अनुयायियों की भूमिका के लिए किया गया है। सीरीज में आश्रम के अनुयायियों और उसके आसपास के माहौल की अहम भूमिका होने के कारण स्थानीय कलाकारों के लिए इसे बड़ा अवसर माना जा रहा है।

एक साथ नजर आएंगे बाबा निराला और भोपा स्वामीः सीरीज में बाबा निराला के सबसे खास सहयोगी भोपा स्वामी का किरदार निभाने वाले चंदन रॉय सान्याल भी चौथे सीजन में नजर आएंगे। वहीं त्रिधा चौधरी एक बार फिर बबीता के किरदार में दिखाई देंगी। दोनों कलाकार फिलहाल जयपुर में शूटिंग कर रहे हैं। सीरीज में अदिति पोहनकर (पम्मी), दर्शन कुमार (उजागर सिंह), अनुप्रिया गोयनका (डॉ नताशा), सचिन श्रॉफ (हुकुम सिंह) और प्रीति सूद (साध्वी माता) की भूमिका में हैं। इनके अलावा कुछ नए कलाकारों की भी एंट्री हुई है। इनमें नीतू चंद्रा श्रीवास्तव, पंखुड़ी गिडवानी, अरमान पारिख, ध्रुव चौधरी और अक्षय ओबेरॉय के नाम शामिल हैं। इससे चौथे सीजन की कहानी में नए किरदारों के जुड़ने की उम्मीद है।

2020 में आया था पहला सीजनः आश्रम सीरीज का पहला सीजन वर्ष 2020 में रिलीज हुआ था। प्रकाश झा के निर्देशन में बनी इस सीरीज में बॉबी देओल ने बाबा निराला का किरदार निभाकर खूब चर्चा बटोरी थी। इसके बाद सीरीज के अगले सीजन भी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय रहे। अब चौथे सीजन की शूटिंग जयपुर में होने से यह शहर एक बार फिर शूटिंग हब के रूप में उभरा है।

'बॉलीवुड चल रहा भेड़चाल', करीना कपूर ने भाई रणबीर कपूर की 'एनिमल' को लेकर ये क्या कह डाला

बॉलीवुड की 'बेबो' करीना कपूर खान ने बॉलीवुड को लेकर बड़ा बयान दिया है। करीना ने अपने भाई रणबीर कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म एनिमल के आधार पर फिल्म इंडस्ट्री को घेरा है। करीना ने साफ कहा है कि बॉलीवुड में 'भीड़ की मानसिकता' है। एक्ट्रेस के कहने का मतलब है कि जब किसी भी जोनर की फिल्म हिट हो जाती है, तो पूरा बॉलीवुड उसी तरह की फिल्म बनाने में जुट जाता है। करीना ने अपनी अपकमिंग फिल्म दायरा के प्रमोशन के दौरान दिए एक इंटरव्यू में यह बात कही है। करीना ने अपने इस इंटरव्यू में साफ कहा है कि एनिमल एक हिंसक फिल्म है, जिसमें मारकाट के बहुत भयंकर सीन है। एक्ट्रेस ने कहा, 'एनिमल ने बॉलीवुड में हिंसक फिल्मों को जन्म दिया है और अब सभी इस तरह की फिल्में बना रहे हैं। हमारे

दर्शक हमारी सोच से कहीं ज्यादा समझदार हैं। उन्हें पता होता है कि कौन सी फिल्म अच्छी है और वे उसे देखना चाहते हैं। इसलिए आज के समय में सिर्फ युवा प्रेम कहानियों की बात नहीं है। ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं'।

एक्ट्रेस ने एनिमल का उदाहरण देते हुए समझाया, 'जैसे 'अभी हिंसा चल रही है, एनिमल चल गई तो चलो सब हिंसा कर लेते हैं। हम सब भेड़चाल में चलते हैं, क्या कहें? फिर कुछ ऐसे फिल्म निमार्ता भी हैं, जो कुछ अलग बनाना चाहते हैं, जो सोचने पर मजबूर करते हैं और जिनके अपने फैंस हैं। मुझे लगता है कि अब चीजें बदल रही हैं। दर्शक अब ट्रेलर देखकर कहेंगे कि हम ये फिल्म देखना चाहते हैं'।

अभिनेत्री ने यह भी बताया कि बदलते दर्शकों के कारण फिल्म निमार्ताओं के लिए सफलता की गारंटी के लिए किसी विशेष फॉमूर्ले या शैली पर निर्भर रहना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि खासकर युवा दर्शक, जो कुछ भी देखते हैं उस पर सवाल उठाने के लिए अधिक इच्छुक हैं और पारंपरिक कहानी कहने के तरीकों से परे कुछ नया चाहते हैं। एक्ट्रेस ने कहा, 'युवा दर्शक सवाल पूछेंगे। अब फिल्म निमार्ता यह कहकर फिल्म नहीं बना सकते कि यह कॉमेडी है, इसलिए लोग इसे जरूर देखेंगे। हर फिल्म 200 करोड़ या 500 करोड़ रुपये नहीं कमाएगी।

तापसी पन्नू स्टारर गांधारी बनी नेटफ्लिक्स पर दूसरी सबसे बड़ी इंडियन ओरिजिनल फिल्म ओपनिंग

तापसी पन्नू की लीडिंग गांधारी ने नेटफ्लिक्स पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसने अपने पहले हफ़्ते में दुनिया भर में 5.9 मिलियन व्यूज रिकॉर्ड किए हैं और इंडियन नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फि ल्मों में दूसरे सबसे ज्यादा ओपनिंग-वीक परफॉर्मर के तौर पर रैंक किया है। 3 सितंबर, 2026 को रिलीज हुई इस एक्शन थ्रिलर ने जाने जान और डार्लिंग्स के ओपनिंग-वीक नंबर को पीछे छोड़ दिया है, और यह सबसे मजबूत इंडियन नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फि ल्मों में से एक बन गई है।

दो पत्ती, जो 25 अक्टूबर, 2024 को रिलीज हुई थी, अपने ओपनिंग वीक में 17 मिलियन व्यूज के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर है। गांधारी 5.9 मिलियन व्यूज के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि जाने जान, जो 21 सितंबर, 2023 को रिलीज हुई थी, ने 4.4 मिलियन व्यूज रिकॉर्ड किए थे। 5 अगस्त, 2022 को प्रीमियर हुई डार्लिंग्स को 411,538 व्यूज मिले।

इस रैंकिंग ने गांधारी को किसी भी इंडियन नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फि ल्म के लिए सबसे मजबूत ओपनिंग-वीक परफॉर्मर में से एक बना दिया है। यह माइलस्टोन तापसी पन्नू की हिंदी एक्शन-थ्रिलर के लिए ऑडियंस की अट्रैक्शन को भी दिखाता है, जिससे फि ल्म के नेटफ्लिक्स रन में एक और बड़ी अचीवमेंट जुड़ गई है।

यह अचीवमेंट तापसी की परफॉर्मेंस, खासकर फि ल्म के एक्शन सीक्वेंस की जबरदस्त तारीफ के बीच आई है। ऑडियंस ने हर फाइट में उनके इंटेंसिटी, फि ज़िकैलिटी और इमोशनल कॉनफि डेंस की तारीफ की है, कई लोगों ने इसे हाल के हिंदी सिनेमा में किसी फीमेल एक्टर की बेस्ट एक्शन परफॉर्मेंस में से एक कहा है।

तापसी के लिए, नंबर 2 रैंकिंग गांधारी के रन में एक और बड़ी अचीवमेंट जोड़ती है, साथ ही हिंदी सिनेमा की लीडिंग फीमेल एक्शन परफॉर्मर में से एक के तौर पर उनकी पोज़िशन को मजबूत करती है। फि ल्म को न सिर्फ. ग्लोबली एक मजबूत ऑडियंस मिली है, बल्कि इसने तापसी को ऐसा एक्शन करने का मौका भी दिया है जिसे ऑडियंस फीमेल-लीड हिंदी सिनेमा के लिए एक नया बेंचमार्क कह रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, बीसीसीआई स्पोर्ट्स एक्ट के दायरे में क्यों नहीं, बोर्ड और सभी राज्य क्रिकेट संघों से मांगा जवाब

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और सभी राज्य क्रिकेट संघों से पूछा है कि उन्हें राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के दायरे में क्यों नहीं लाया जाना चाहिए। अदालत ने बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों के पदाधिकारियों की सेवा शर्तों को भी इस कानून के तहत लाने को लेकर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने बीसीसीआई से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान यह सवाल उठाया। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना भी शामिल रहे। यह मामला 2014 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और समय-समय पर इससे जुड़े अलग-अलग आवेदन अदालत के सामने आते रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों की ओर से पेश वकीलों से निर्देश लेकर यह बताने को कहा कि उनके पदाधिकारियों के कार्यकाल और सेवा की शर्तें 2025 में लागू हुए राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम के तहत क्यों नहीं होनी चाहिए। अदालत के इस सवाल से यह मुद्दा महत्त्वपूर्ण हो गया है कि देश में क्रिकेट का संचालन करने वाली संस्था बीसीसीआई और उसके राज्य संघों पर नए खेल शासन कानून के प्रावधान किस तरह लागू होंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई के कामकाज और उसमें सुधार से जुड़ी याचिका वर्ष 2014 से चल रही है।

क्या केबीसी छोड़ेगें अमिताभ बोलें- शो को होस्ट करना मुश्किल है, बहुत दिल तोड़ने वाला अनुभव रहा है

अमिताभ बच्चन अपने ब्लॉग के माध्यम से लगातार प्रशंसकों से संवाद बनाए रखते हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन के विभिन्न पहलुओं को साझा करते हैं। हाल ही में ब्लॉग पोस्ट में उन्होंने लोकप्रिय टीवी शो डइउ ने अनुभवों पर चर्चा की। उन्होंने विशेष रूप से उन प्रतिभागियों का जिक्र किया जो मंच पर अपने जीवन के बेहद निजी और दुखद किस्से सुनाते हैं। बिग बी ने स्वीकार किया कि कई बार प्रतियोगियों के इन संघर्षों और दर्दभरी कहानियों को सुनना बेहद भावुक और दिल तोड़ने वाला होता है।

अमिताभ बच्चन ने लिखा– कुछ कंटेस्टेंट इतनी गंभीर निजी कहानियाँ लेकर आते हैं कि न

सिर्फ उनके लिए अपनी भावनाओं को संभालना, बल्कि शो को होस्ट करना जारी रखना भी मुश्किल हो जाता है, मैं इस बारे में और ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि इससे उस समझ पर असर पड़ेगा जो एक होस्ट चैनल को देता है लेकिन यह एक दिल तोड़ने वाला अनुभव रहा है। इस रहस्यमयी और इमोशनल नोट ने फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है। क्विज शो की बात करें तो, 'कौन बनेगा करोड़पति' सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे प्रसारित होता है। डइउ ब्रिटिश शो 'हू वांट्स टू बी ए मिलियनेयर?' के भारतीय वर्शन के तौर पर शुरू हुआ था। यह अमिताभ बच्चन का पहला टीवी अपीयरेंस भी था और इसने उनके करियर को नई जिंदगी दी। समय के साथ, केबीसी सिर्फ. एक क्विज शो से कहीं ज्यादा बन गया। कंटेस्टेंट की दिल को छू लेने वाली कहानियों और बच्चन के मशहूर डायलॉग लॉक किया जाए के साथ, यह शो लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया।

अमिताभ बच्चन का वर्कफ्रंट : बिग बी के काम की बात की जाए तो वो जल्द ही फिल्म कल्कि 2898 एडी के दूसरे पार्ट में नजर आएंगे।

बॉलीवुड के1980 का क्लासिक लुक फिर लौटा

इंस्टाग्राम का 80 के दशक का फोटो ट्रेंड एक वायरल एआई पिल्टर ट्रेंड है, जिसमें यूजर्स अपनी मॉडर्न तस्वीरों को 1980 के दशक के रेट्रो भारतीय पोर्ट्रेट (विंटेज बॉलीवुड फि ल्म लुक या क्लासिक फैमिली एल्बम स्टाइल) में बदलते हैं। यूजर्स चैट जीपीटी में अपनी साफ फोटो अपलोड करते हैं और '80 के दशक का स्टाइल के लिए खास प्रॉम्प्ट देते हैं। अलग-अलग देखें तो यह मामूली लग सकता है। लेकिन कुल मिलाकर, यह कुछ और ही है। जैसे-जैसे जेनरेटिव अक हमारे बनाने और इस्तेमाल करने के तरीकों में घुल-मिल रहा है, सवाल सिर्फ. क्षमता का नहीं रह जाता- यह जागरूकता, इरादे और हम किसे सामान्य मानते हैं, इस बारे में भी है। इंस्टाग्राम का '80 फोटो ट्रेंड हमें उस दौर की याद दिलाने का एक और तरीका खोज लिया है जिसे हमने असल में कभी नहीं जिया। हाल ही में इंस्टाग्राम पर 80 के दशक की एआई इमेज की बाढ़ आ गई है, जिसमें आम तस्वीरों को खास स्टाइल में बदलकर पुराने जमाने जैसा और आकर्षक दिखाया जाता है। इसमें इंस्टाग्राम की मुख्य भूमिका है क्योंकि सही प्रॉम्प्ट के साथ इस्तेमाल करने पर यह पहले से मौजूद तस्वीरों को रेट्रो इमेज में बदल सकता है। महिलाओं को रंग-बिरंगी और शानदार साड़ियों में दिखाया जा रहा है, जिनके बाल सुंदर कर्ली और 80 के दशक के स्टाइल में ब्लो-ड्राय किए हुए हैं, साथ ही माथे पर सजावटी बैंग्स (बालों की लटें) भी हैं। वहीं दूसरी ओर, पुरुषों को ढीली शर्ट, हाई-वेस्ट पैंट, घनी मूंछों और खास स्टाइल वाले बालों में देखा जा सकता है।

सेमीफाइनल में बांग्लादेश से भिड़ेगा भारत, आज दुबई में खेला जाएगा एशिया कप का मुकाबला

नई दिल्लीः वूमंस एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल्स का शेड्यूल कन्फर्म हो चुका है। इस टूर्नामेंट का आखिरी लीग मैच मेजबान यूएई और बांग्लादेश के बीच खेला गया। उस मैच में बांग्लादेश की टीम ने बाजी मारी और सेमीफाइनल का टिकट कटाया। इस तरह टॉप 4 की सभी टीमें फाइनल हो गईं। टीम इंडिया ने सबसे पहले सेमीफाइनल का टिकट कटाया था, जबकि इसके बाद श्रीलंका ने दूसरे ग्रुप से टॉप 4 में जगह सुनिश्चित की थी। वहीं, पाकिस्तान की टीम ने टीम इंडिया के ग्रुप से सेमीफाइनल में एंट्री मारी और अब बांग्लादेश की टीम ने भी इन तीनों को ज्वाइन कर लिया है।

वूमेन्स एशिया कप 2026 के ग्रुप ए से टीम इंडिया और पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंची है, जबकि ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश ने टॉप 4 में एंट्री की है। ऐसे में दोनों सेमीफाइनल दो अलग-अलग ग्रुप वाली टीमों के बीच होंगे। टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच मुकाबला गुरुवार 10 सितंबर को दुबई में भारतीय समयानुसार शाम 8 बजे होंगे। वहीं, दूसरा सेमीफाइनल श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच आयोजित होगा, जो शुक्रवार 11 सितंबर को दुबई में ही खेला जाएगा।

कुशाग्र की इंडिया-ए टीम में एंट्री, दलीप ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन का मिला इनाम, ऑस्ट्रेलिया-ए से भिड़ेंगे

नई दिल्लीः ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ होने वाले मल्टी-डे और वनडे मैचों के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भारत-ए टीम का ऐलान कर दिया है। मल्टी-डे मुकाबलों के लिए टीम की कमान देवदत्त पडिक्कल के हाथों में सौंपी गई है। वहीं, वनडे मैचों के लिए ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बनाया गया है। वनडे फॉर्मेट की टीम में हार्दिक पांड्या को भी शामिल किया गया है। हालांकि, हार्दिक इस सीरीज में तभी हिस्सा ले पाएंगे, जब वह अपना फिटनेस टेस्ट पास करने में सफल रहेंगे। इंडिया ए को ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दो मल्टी-डे मुकाबले और

तीन वनडे मैच खेलने हैं, जिसकी शुरूआत 22 सितंबर से होनी है। मल्टी-डे मुकाबलों के लिए साई सुदर्शन की वापसी हुई है। सुदर्शन इंजरी के कारण श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हिस्सा नहीं ले सके थे। इसके साथ ही अमन मोखड़े, आयुष पांडे को भी जगह दी गई है। दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन की तरफ से शानदार प्रदर्शन करने वाले कुमार कुशाग्र को भी टीम में शामिल किया गया है।

यश राठौड़ टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं, जबकि शम्स मुलानी और तनुश कोटियान को भी मल्टी-डे मुकाबलों के लिए टीम में रखा गया है। तुषार देशपांडे, अंशुल कंबोज और प्रफुल्ल हिंगे तेज गेंदबाजी की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। प्रफुल्ल ने आईपीएल 2026 में अपनी गेंदबाजी से काफी प्रभावित किया था। एन जगदीशन मल्टी-डे मैचों में विकेटकीपर की भूमिका निभाते नजर आएंगे। वनडे टीम में देवदत्त पडिक्कल को उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रियांश आर्या के साथ साई सुदर्शन को भी वनडे टीम में शामिल किया गया है। रजत पाटीदार, कुमार कुशाग्र और नमन धीर मध्यक्रम की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं, शानदार फॉर्म में चल रहे प्रभसिमरन सिंह से भी इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। दूसरा मल्टी-डे मुकाबला 29 सितंबर से खेला जाएगा। वहीं, वनडे सीरीज का आगाज छह अक्तूबर से होगा। दूसरा मुकाबला नौ अक्तूबर और अंतिम मैच 11 अक्तूबर को खेला जाएगा।

वन-डे मैचों के लिए इंडिया स्क्वॉड : प्रियांश आर्य, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल (उपकप्तान), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), रजत पाटीदार, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, विपराज निगम, अर्शिन कुलकर्णी, अरशद खान, नमन धीर, हार्दिक पांड्या*, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), गुरजापनीत सिंह और यश ठाकुर।

मल्टी-डे मुकाबलों में इन खिलाड़ियों की एंट्रीः अमन मोखड़े, आयुष पांडे, देवदत्त पडिक्कल (कप्तान), साई सुदर्शन (उपकप्तान), यश राठौड़, शेख रशीद, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, तनुष कोटियान, तुषार देशपांडे, अंशुल कंबोज, प्रफुल्ल हिंगे, एन जगदीशन (विकेटकीपर), नचिकेत भुटे, वी वैश्य*।

न्यूज ब्रीफ

बंगलुरु के स्टार्टअप प्रनोस फ्यूजन को बड़ी कामयाबी, कंपनी के टोकामक प्रज्ञा ने पहली बार बनाया प्लाज्मा

एजेंसी/ बंगलुरुः भारत में न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च को लेकर प्राइवेट सेक्टर ने एक बड़ा कदम उठाया है। बंगलुरु की स्टार्टअप प्रनोस फ्यूजन ने अपने टोकामक प्रज्ञा (पीआरएजीवाईए) में पहली बार प्लाज्मा बनाया है। करीब 40 सेंटीमीटर रेडियस वाले इस टोकामक को कंपनी ने लगभग आठ महीने में तैयार किया है। इसका इस्तेमाल प्लाज्मा को कंट्रोल करने, उसकी जांच करने और फ्यूजन से जुड़ी दूसरी तकनीकों को टेस्ट करने के लिए किया जाएगा। प्रज्ञा का काम अभी बिजली बनाना नहीं है। यह एक तरह की टेस्ट मशीन है, जिस पर कंपनी लगातार प्रयोग करेगी। कंपनी इसे करीब 20 साल तक चलाने की योजना बना रही है। इस दौरान हर साल करीब 3,000 प्लाज्मा शॉट लेने का लक्ष्य है। यानी रोजाना करीब 10 से 12 बार प्लाज्मा बनाकर उससे जुड़ा डाटा इक्ा किया जाएगा। इस डाटा से आगे बड़े फ्यूजन रिएक्टर बनाने में मदद मिल सकती है। टोकामक एक ऐसी मशीन है, जिसमें बहुत गर्म प्लाज्मा को चुंबकीय ताकत की मदद से कंट्रोल किया जाता है। फ्यूजन के लिए गैस को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है। इतनी गर्मी में गैस प्लाज्मा में बदल जाती है। फ्यूजन में छोटे परमाणुओं को आपस में जोडकर एनर्जी बनाने की कोशिश की जाती है। सूरज में भी इसी तरह की प्रक्रिया से एनर्जी बनती है। वैज्ञानिक कई साल से धरती पर इस प्रक्रिया को कंट्रोल करके एनर्जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

2030 तक बड़ा रिएक्टर बनाने का लक्ष्यः प्रनोस फ्यूजन कंपनी की योजना 2027 तक एचटीएस मैग्नेट को चालू करने की है। इसके बाद वह 2030 तक प्रनीक नाम का नेट एनर्जी गेन रिएक्टर बनाने का लक्ष्य रखती है। नेट एनर्जी गेन का आसान मतलब है कि फ्यूजन से जितनी एनर्जी मिले, वह उसे चलाने में लगाई गई एनर्जी से ज्यादा हो। हालांकि, यह अभी कंपनी का लक्ष्य है। प्रज्ञा खुद नेट एनर्जी गेन रिएक्टर नहीं है। यहां बता दें कि कंपनी प्रज्ञा के जरिए सिर्फ तकनीक पर काम नहीं करना चाहती। वह ज्यादा से ज्यादा फ्यूजन वैज्ञानिक और प्लाज्मा फिजिसिस्ट तैयार करने की भी योजना बना रही है। इसके लिए प्रज्ञा पर लंबे समय तक प्रयोग किए जाएंगे, ताकि वैज्ञानिकों और छात्रों को फ्यूजन तकनीक को समझने और उस पर काम करने का मौका मिले। उम्मीद है कि इससे भारत में फ्यूजन रिसर्च और इस क्षेत्र से जुड़े काम को बढ़ावा मिलेगा।

मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से भी किया बाहर, अशोक सिद्धार्थ पर भी साधा निशाना

लखनऊः बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) प्रमुख मायावती ने गुरुवार को अपने भतीजे और पूर्व राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को पार्टी से पूरी तरह से मुक्त करने की घोषणा की है। साथ ही उन्होने अपने समधी अशोक सिद्धार्थ के राजनीति से संन्यास लेने के फैसले को अति-देर से उठाया गया सही कदम बताया है। मायावती ने गुरुवार को एक्स पर 10 बिंदुओं में विस्तृत पोस्ट कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने लिखा कि अशोक सिद्धार्थ अगर यह फैसला काफी पहले ले लेते तो बसपा, बहुजन समाज, बहुजन मूवमेंट और उनके दामाद आकाश आनंद को लगातार विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता और न ही उन्हें विधानसभा आम चुनाव व खासकर यूपी में पांचवीं बार सरकार बनाने की तैयारियों के बीच कड़े फैसले लेने पड़ते। बसपा प्रमुख ने कहा कि बसपा की अंबेडकरवादी राजनीति की परम्परा त्याग, तपस्या, संघर्ष और निजी-पारिवारिक स्वार्थ से दूर रहने की रही है, जिसे कांशीराम जी की तरह वह भी समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि महान लक्ष्य के लिए बड़ी कुबार्नी की जरूरत होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि अशोक सिद्धार्थ को अगर सच में आकाश आनंद के उज्वल भविष्य और पार्टी हित की चिंता होती तो वे बिना देरी किए तुरंत संन्यास की घोषणा कर देते, जिससे आकाश की सक्रियता सुनिश्चित हो सकती थी। ऐसा न करना उनकी नीयत में खोट और अभिलाषा बरकरार रहने को साबित करता है। मायावती ने आकाश आनंद पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अपने करियर से अधिक अपने ससुर के प्रति लगाव दिखाया है और बसपा प्रमुख के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उनके ही भलाई के लिए किए गए पोस्ट को रीपोस्ट तक करना उचित नहीं समझा, जबकि पहले वे वफादारी का सबूत देने के लिए पोस्ट रीपोस्ट करते रहे हैं। इसी आधार पर मायावती ने घोषणा की कि जैसे दिनांक 3 सितंबर 2026 को आकाश आनंद को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के अति-महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया था, उसी प्रकार अब उन्हें पार्टी से भी आज से पूरी तरह से फ्री (आजाद) कर दिया गया है। यदि वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो वे स्वतंत्र हैं।

छात्र को मजिस्ट्रेट के नोटिस पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई बोले-

नोटिस भेजने की हिम्मत कैसे हुई

,7,लीड

नई दिल्लीः दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय (जीबीयू) के एक छात्र को नोटिस जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने सख्त नाराजगी जताते हुए बुधवार को कहा कि वह ग्रेटर नोएडा की मजिस्ट्रेट से इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण मांगेगी। चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अगुवाई वाली तीन जजों की पीठ ने दो टूक सवाल किया कि जब कोर्ट ने पहले ही छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा रखी थी, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने ऐसा नोटिस जारी करने की हिम्मत कैसे की?

वकील ने उठाया छात्र को मिले 5 लाख के बॉन्ड नोटिस का मुद्दा : यह मामला वरिष्ठ वकील विश्वजीत भट्टाचार्य ने बेंच के समक्ष उठाते हुए दलील दी कि प्रशासन छात्रों के मन में डर का माहौल पैदा कर रहा है। उन्होंने बताया कि शीर्ष अदालत ने 1 सितंबर को साफ निर्देश दिया था कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।

इसके बावजूद ग्रेटर नोएडा आयुक्तालय के तृतीय कार्यकारी मजिस्ट्रेट कार्यालय ने सेकेंड ईयर के छात्र अक्षत त्रिपाठी को शांति व्यवस्था के नाम पर 5 लाख रुपये का मुचलका (बॉन्ड) भरने का नोटिस थमा दिया। हालांकि विवाद बढ़ने और मीडिया में खबरें आने के बाद पुलिस ने इस नोटिस को वापस ले लिया, लेकिन वकील ने इसे सीधे तौर पर अदालत की अवमानना करार दिया।

युवाओं के खिलाफ ऐसी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं, मजिस्ट्रेट को देना होगा जवाब:सीजेआई : याचिकाकर्ता की दलीलों पर सहमति जताते हुए सीजेआई सूर्य कांत ने कड़े शब्दों में कहा कि देश के युवाओं के खिलाफ इस तरह की मनमानी कार्रवाई का कोई सवाल ही नहीं उठता। कोर्ट का आदेश पूरी तरह से स्पष्ट था और उसका उल्लंघन हैरान करने वाला है। उन्होंने वकील को तमाम तथ्य रिकॉर्ड पर रखने के निर्देश देते हुए कहा कि अदालत संबंधित मजिस्ट्रेट से जवाब तलब करेगी और उन्हें अपनी बात रखने का मौका देगी। पीठ के सदस्य जस्टिस बागची द्वारा नोटिस वापसी पर पूछे गए सवाल पर वकील ने कहा कि उन्हें इसकी औपचारिक जानकारी नहीं मिली है, केवल मीडिया के जरिए पता चला है।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने पर पुलिस ने कसा था शिकंजाः पूरा विवाद जीबीयू के छात्र अक्षत त्रिपाठी को मिले नोटिस से जुड़ा है। पुलिस का आरोप था कि छात्र ने जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अन्य विद्यार्थियों को उकसाया था। हालांकि छात्र ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया था कि उसने केवल शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन में हिस्सा लिया था और उस वक्त उसकी कोई क्लास भी नहीं चल रही थी। पुलिस के मुताबिक यह कोई सजा नहीं बल्कि शांति बनाए रखने के लिए एक एहतियाती बॉन्ड नोटिस था, जिसे अब वापस ले लिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अदालत के आदेशों की खुली अनदेखी मानते हुए जांच का दायरा बढ़ा दिया है।

2030 तक एआई इंसानों को मार देगा , रिसर्चर की चेतावनी के बाद दुनिया में खलबली

नई दिल्ली/एजेंसीः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की बढ़ती क्षमताओं को लेकर एक तरफ जहां दुनिया में उत्साह है, वहीं दूसरी ओर इसके संभावित खतरों को लेकर चिंता भी गहराती जा रही है। एक ओर ओपन एआई ने दावा किया है कि उसके एआई सिस्टम ने करीब 90 वर्षों से अनसुलझी नेवियर-स्टोक्स समस्या का समाधान खोज लिया है, वहीं एंथ्रोपिक के एक शोधकर्ता के इस्तीफे और उसके बाद कंपनी के वरिष्ठ एआई सुरक्षा शोधकर्ता की चेतावनी ने बहस को और तेज कर दिया है।

एआई हम सबको मार देगाः क्लाउड बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक के एक रिसर्चर ने इस्तीफा देते हुए कहा है कि इस दशक के अंत तक एआई हम सबको मार सकता है। जो लोग एआई विकसित कर रहे हैं, उन्हें इसके बारे में पता है। एंथ्रोपिक के रिसर्चर जैकब कॉक्सन ने 9 सितंबर को इस्तीफा दिया और चेतावनी दी कि एआई सभी इंसानों को खत्म कर सकता है

एंथ्रोपिक के शोधकर्ता ने दिया इस्तीफाः इसी बीच एआई कंपनी एंथ्रोपिक के शोधकर्ता जैकब कॉक्सन ने इस्तीफा देते हुए एआई के भविष्य को लेकर बेहद गंभीर चेतावनी दी है। कॉक्सन ने आरोप लगाया कि एंथ्रोपिक और ओपनएआई जैसी कंपनियां तेजी से खुद को सुधारने वाली सुपरइंटेलिजेंट एआई प्रणालियां विकसित करने की दौड़ में आगे बढ़ रही हैं और सुरक्षा के मुकाबले क्षमता को प्राथमिकता देने का खतरा है। उन्होंने दावा किया कि एआई विकसित करने वाले कुछ लोग निजी तौर पर इस तकनीक से मानव अस्तित्व को होने वाले खतरे को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं।

कॉक्सन की चेतावनी को एंथ्रोपिक के अलाइनमेंट साइंस प्रमुख इवान हुबिंगर ने भी सार्वजनिक रूप से समर्थन दिया। हुबिंगर ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर अगले दशक में एआई द्वारा सभी इंसानों के खत्म होने की संभावना 10 प्रतिशत से अधिक लगती है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि सुपरइंटेलिजेंट एआई को मानव हितों के अनुरूप बनाए रखने के लिए कंपनी के पास अभी स्पष्ट और पर्याप्त समाधान नहीं है।

88 घंटे में मिली गणितीय सफलता : चैटजीपीटी बनाने वालीः ओपनएआई ने 8 सितंबर को दावा किया कि उसके आंतरिक एआई सिस्टम ने नेवियर-स्टोक्स अस्तित्व और स्मूथनेस समस्या का समाधान तैयार किया है। यह गणित की सात मिलेनियम प्राइज समस्याओं में शामिल है और करीब 90 वर्षों से अनसुलझी थी। कंपनी के मुताबिक, एआई एजेंटों ने 5 सितंबर को लगभग 88 घंटे में समाधान तक पहुंच बनाई, जबकि उसके औपचारिक सत्यापन में अतिरिक्त 17 घंटे लगे।

ओपनएआई के अनुसार, इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में एआई एजेंटों को अलग-अलग तरीकों से समस्या पर काम कराया गया और बाद में उनके निष्कर्षों को एक साथ जोड़ा गया। कंपनी ने समाधान का लिखित विवरण और लीन में औपचारिक प्रमाण भी जारी किया है। हालांकि, गणितीय समुदाय में इस दावे की स्वतंत्र समीक्षा महत्वपूर्ण होगी।

एआई की साइबर क्षमता भी बढ़ीः एआई की बढ़ती स्वायत्तता को लेकर चिंता का एक बड़ा कारण उसकी साइबर सुरक्षा क्षमताओं में तेजी से हो रहा विकास है। ओपनएआई के नए जीपीटी-6 एस्ट्रा के बारे में कंपनी ने खुद कहा है कि यह ऐसे मॉडल स्तर तक पहुंच गया है, जहां उचित टूल और एक्सेस मिलने पर यह इंसानी मार्गदर्शन के बिना पहले से अज्ञात सुरक्षा खामियों की पहचान कर उनका इस्तेमाल करने के तरीके विकसित कर सकता है। कंपनी के सुरक्षा परीक्षणों में एस्ट्रा ने कुछ मामलों में जीरो-डे कमजोरियों की खोज और उनके इस्तेमाल की क्षमता दिखाई।

हालांकि, ओपनएआई का कहना है कि इन क्षमताओं के साथ सुरक्षा उपायों को भी मजबूत किया गया है और उत्पादन स्तर पर मॉडल पर कई प्रतिबंध लागू किए गए हैं। कंपनी ने यह भी कहा है कि उसके परीक्षणों में एस्ट्रा पिछले मॉडल की तुलना में कई तरह के जोखिमपूर्ण व्यवहार से बेहतर तरीके से बचता है।

एआई की दौड़ में सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौतीः एआई कंपनियों के बीच अधिक शक्तिशाली और स्वायत्त मॉडल विकसित करने की होड़ तेज हो चुकी है। एक तरफ ये मॉडल गणित, कोडिंग, विज्ञान और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में इंसानों की क्षमता बढ़ाने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यदि एआई की क्षमताएं मानव नियंत्रण और सुरक्षा उपायों से अधिक तेजी से बढ़ीं तो जोखिम भी बढ़ सकता है। फिलहाल मानवता के लिए एआई से अस्तित्व संबंधी खतरे की संभावनाओं को लेकर विशेषज्ञों में एक राय नहीं है। लेकिन ओपनएआई की गणितीय उपलब्धि और एंथ्रोपिक के अंदर से उठ रही सुरक्षा संबंधी आवाजें यह जरूर संकेत देती हैं कि एआई की अगली दौड़ केवल ज्यादा शक्तिशाली मॉडल बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित और नियंत्रित रखने की भी होगी।

वंदे मातरम् पर इंडिया गठबंधन में बढ़ी रार

कांग्रेस की फारुख और उमर को सलाह,पार्टी का साथ दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा, शर्तें नहीं

संवाददाता

नई दिल्लीः जम्मू-कश्मीर में वंदे मातरम् के पूर्ण संस्करण को लेकर कांग्रेस और उसकी गठबंधन सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के बीच मतभेद सामने आ गए हैं। श्रीनगर में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में वंदे मातरम् का पूर्ण संस्करण गाए जाने पर कांग्रेस की आपत्ति ने एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया है। सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस से कहा है कि वह गठबंधन सहयोगियों पर अपनी शर्तें नहीं थोप सकती। बता दें कि जम्मू-कश्मीर के पहले अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन के दौरान वंदे मातरम् के सभी छह अंतरे गाए गए। इस कार्यक्रम में फारुख अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। साथ ही, जब राष्ट्रीय गीत के सभी छह अंतरे गाए जा रहे थे, तब इसके सम्मान में फारुख अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला खड़े रहे। फिल्म फेस्टिवल में गाए जा रहे गीत के फुल वर्जन का वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अपनी सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को सलाह दी है कि वे गीत के छोटे वर्जन का ही इस्तेमाल करने के मामले में पार्टी का साथ दें।

वंदे मातरम् का फुल वर्जन उस मिली-जुली और अनेकता वाली सोच के साथ मेल नहीं खाता, जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत के लिए की थी और जिसे उन्होंने आगे बढ़ाया था। इस दावे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगियों पर शर्तें नहीं थोप सकती। एनसी नेता बशीर अहमद ने कहा कि गठबंधन सहयोगी के तौर पर आप यह तय नहीं कर सकते कि क्या गाना है या कितना गाना है। वेणुगोपाल को पोस्ट करने का अधिकार है, लेकिन वे अपनी बात थोप नहीं सकते। यह लोगों की पसंद है। हम लोगों पर कुछ भी थोपे जाने के खिलाफ हैं।

भाजपा ने बोला हमलाः भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसे 21वीं सदी की मुस्लिम लीग बताया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् के संपूर्ण गायन को लेकर संसद द्वारा पारित नियम के बावजूद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर जो आपत्ति की है उसने उसका असली चेहरा सामने ला दिया है। कांग्रेस के सहयोगी दलों, यहां तक कि एनसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी संपूर्ण वंदे मातरम् के गायन में सम्मिलित हो रहे हैं, मगर कांग्रेस को आपत्ति है।

राशन डीलरों की परेशानी पर राजद का वार, कमीशन और बकाया भुगतान को लेकर उठे सवाल

पटनाः राजद नेता ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पूर्व जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के कमीशन में 47 रुपये की वृद्धि की घोषणा की गई थी। एक वर्ष बीत जाने के बावजूद यदि बढ़ी हुई राशि का भुगतान नहीं हुआ है तो उसे तत्काल प्रभाव से लागू कर बकाया राशि का भुगतान कराया जाना चाहिए। यादव ने बिहार राज्य खाद्य निगम के गोदामों में कथित भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं घटतौली की शिकायतों पर कठोर कार्रवाई करने तथा पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की मांग की। उन्होंने माप-तौल, घटतौली, ई-पॉस मशीन, सर्वर और अन्य तकनीकी समस्याओं का वास्तविक समय में समाधान सुनिश्चित करने को कहा, ताकि तकनीकी खामियों का खामियाजा जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं और लाभुकों को नहीं भुगतना पड़े। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था से जुड़े अनावश्यक प्रशासनिक दबाव एवं दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने तथा विक्रेताओं की वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए जिला एवं प्रखंड स्तर पर प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था बनाने की मांग की। राजद नेता ने जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सरकार, विभागीय अधिकारियों और उचित मूल्य विक्रेता संघ के प्रतिनिधियों की नियमित त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने का भी आग्रह किया। श्री यादव ने मुख्यमंत्री से आठ सूत्री मांगों पर तत्काल सकारात्मक एवं समयबद्ध निर्णय लेने का आग्रह करते हुए विश्वास जताया कि राज्य सरकार जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं की जायज मांगों पर संवेदनशीलता एवं गंभीरता से विचार कर शीघ्र समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाएगी।

भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी श्रीलंका की जमीन राष्ट्रपति दिसानायके ने राजनाथ को दिया सुरक्षा का भरोसा

नई दिल्ली/एजेंसीः श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने दोटूक कहा है कि वह अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत-विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने देंगे। बुधवार को दिसानायके ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक में भारत को भरोसा दिलाया कि कोलंबो कभी भी अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा के लिए नुकसानदेह गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा। उनका इशारा हंबनटोटा बंदरगाह की ओर था, जिसे 2017 में 99 साल की लीज पर चीन के नियंत्रण में सौंप दिया गया था। चीन वहां कंटेनर क्षमता विकसित कर रहा है और उस जमीन का इस्तेमाल सामरिक और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कर रहा है। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बहुआयामी संबंधों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा की।

उन्होंने कहा कि सभ्यतागत संबंध, करीबी पड़ोसी और समुद्री साझेदार के रूप में भारत और श्रीलंका क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के साथ-साथ दोनों देशों के विकास और लोगों के कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति दिसानायके को शुभकामनाएं दीं और कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत ऐतिहासिक एवं सभ्यतागत संबंधों तथा परस्पर आवागमन पर आधारित गहरी मित्रता है। राष्ट्रपति दिसानायके ने रक्षा मंत्री का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी मुलाकातों को याद किया और दोहराया कि श्रीलंका अपने क्षेत्र का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के प्रतिकूल किसी भी गतिविधि के लिए कभी नहीं होने देगा।

तीन समझौतों पर दस्तखतः दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए तीन समझौतों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें श्रीलंकाई वायुसेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारत-निर्मित एयर-डिफेंस गन को आधुनिक बनाने का समझौता भी शामिल है। दोनों नेताओं ने द्वीपीय देश में भारतीय सेना द्वारा बनाए गए तीन बेली पुलों का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए छह एल70 गन को अपग्रेड करने और दोनों देशों के नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) और नेशनल डिफेंस कॉलेज के बीच सहयोग के लिए एमओयू का आदान-प्रदान किया।

राजनाथ का श्रीलंका से समुद्री सहयोग बढ़ाने का आह्वानः रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंद महासागर क्षेत्र में सामूहिक सुरक्षा और समृद्धि के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, नौवहन की स्वतंत्रता, अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान और निर्बाध समुद्री व्यापार को जरूरी बताते हुए भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को उभरती समुद्री चुनौतियों के गंभीर खतरा बनने से पहले उनसे मिलकर निपटने के लिए नए प्रोटोकॉल, कौशल और अनुभव साझा करने होंगे।

ईरान का अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल अटैक, ए-10 का पंख टूटा, 8एफ-15 लड़ाकू विमान भी क्षतिग्रस्त

तेहरान /एजेंसीःईरान और अमेरिका के बीच जारी सैन्य टकराव अब मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिए भी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। जॉर्डन स्थित एक प्रमुख अमेरिकी एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले के दौरान कई अमेरिकी लड़ाकू विमानों के क्षतिग्रस्त होने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, हमले में वॉरथॉग के नाम से मशहूर अ-10 थंडरबोल्ट का एक पंख तक टूट गया, जबकि करीब आठ ऋ15 लड़ाकू विमानों को भी नुकसान पहुंचा।

सीबीएस की रिपोर्टर जेनिफर जैकब्स ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बताया कि मुवाफक साल्टी एयर बेस पर ईरानी हमले के दौरान एक अ-10 थंडरबोल्ट

बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। वहीं, करीब आठ ऋ15 लड़ाकू विमानों को मामूली नुकसान पहुंचा, जिन्हें बाद में दोबारा सेवा में शामिल कर लिया गया। यह हमला जॉर्डन के मुबाक्क साल्टी एयर बेस पर हुआ, जिसे अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए महत्वपूर्ण एयरपावर हब के रूप में इस्तेमाल करता है। रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी मिसाइल हमले से बचाव के लिए जॉर्डन में तैनात अमेरिकी बलों ने 30 से अधिक पैट्रियट मिसाइलें दागीं। जॉर्डन की सेना के मुताबिक, ईरान की ओर से कुल 20 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई थीं। इनमें से 18 को उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने हवा में ही नष्ट कर दिया, जबकि दो मिसाइलें आबादी वाले क्षेत्रों से दूर खुले इलाकों में जाकर गिरीं। सेना ने कहा कि हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए के अनुसार, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी अल-अजराक सैन्य अड्डे को निशाना बनाने का दावा किया है। गार्ड्स ने इसे अपने सैन्य अभियान का हिस्सा बताते हुए बेस पर बड़े पैमाने पर मिसाइलें दागने की बात कही है।

न्यूज IN ब्रीफ

वरीय कांग्रेस नेता अवध नारायण प्रसाद बने अनुसूचित जाति विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष

बिनय मिश्रा : झारखंड सरकार के लोकप्रिय, कर्मठ एवं बेहतर कार्यों के लिए पहचाने जाने वाले अवध नारायण प्रसाद को उनके बेहतर कार्य दक्षता और संगठन के प्रति समर्पण और कार्यकताओं के बीच व्यापक रूप से उत्साह भरने की निरंतर प्रयास को देखते हुए उन्हें महत्वपूर्ण जवाबदेही दी गई है और इस क्रम में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस झारखंड प्रदेश के अनुसूचित जाति विभाग का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है उनके इस पद पर मनोनयन के पश्चात पार्टी के वरीय नेताओं ने उन्हें शुभ कामना और बधाई दी है। वहीं उनके मनोनयन के पश्चात कार्यकताओं में उत्साह देखा जा रहा है। श्री प्रसाद ने पार्टी के आला कमान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि- उन्हें जो महत्वपूर्ण जवाबदेही सौंपी गई है उस पर वे खरा उतरने का प्रयास करेंगे।

बाढ़ के बीच राशन वितरण में मनमानी का आरोप, पांच किलो की जगह चार किलो अनाज देने की शिकायत

बिहार/सारण : ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण को लेकर उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। आरोप है कि सरकारी निर्देश के अनुसार प्रत्येक राशन कार्डधारी को प्रति इकाई पांच किलोग्राम राशन दिया जाना है, लेकिन कई राशन वितरण केंद्रों पर लाभुकों को महज चार किलोग्राम ही अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि एक ओर बाढ़ के कारण खाद्य सामग्री की कमी और आर्थिक संकट की स्थिति बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर राशन वितरण में कथित कटौती से गरीब और जरूरतमंद परिवारों की परेशानी और बढ़ गई है। आरोप यह भी है कि कुछ राशन विक्रेताओं द्वारा पांच किलोग्राम की जगह चार किलोग्राम राशन ही दिया जा रहा है और इसे सरकारी आदेश बताकर लाभुकों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है।

भीम चूल्हा रेलवे टनल के पास अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद

मेदिनीनगर : मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के भीम चूल्हा रेलवे टनल के समीप गुरुवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पाकर मोहम्मदगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर मृतक की पहचान कराने में जुटी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मृतक के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी मिलने पर तत्काल मोहम्मदगंज थाना को सूचना दें, ताकि उसके परिजनों तक सूचना पहुंचाई जा सके।

सड़क हादसे में 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत, परिजनों ने बाइक से जानबूझकर टक्कर मारने का लगाया आरोप

मेदिनीनगर : नावाबाजार थाना क्षेत्र के कंडा गांव में बुधवार रात करीब आठ बजे अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 55 वर्षीय धर्मेंद्र साव गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान कंडा गांव निवासी स्वर्गीय नागेश्वर साव के पुत्र धर्मेंद्र साव के रूप में हुई है।
परिजनों के अनुसार, धर्मेंद्र साव बुधवार शाम कंडा स्थित अपने पुराने घर गए थे। रात में नए घर लौटने के दौरान गांव की सड़क पर यह हादसा हुआ। हालांकि, परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्हें किसी व्यक्ति ने मोटरसाइकिल से जानबूझकर टक्कर मारी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी है।

कार्ड धारियों को कम अनाज मिलने से होती है सैंकड़ों टन की कालाबाजारी

सारण : बाढ़ प्रभावित सारण जिले का गंगा दियारा इलाका आपदा प्रबंधन विभाग के बड़बोलेपन से ही सिर्फ पीड़ित नही है, इस संकट के समय डीलरों की मनमानी से उनकी पीड़ा और बढ़ गई है। सच यह है कि डीलरों की मनमानी स्थाई स्वरूप ले चुकी है और उनका दावा यह है कि निर्धारित मात्रा से कम अनाज देने का निर्देश सरकार की ओर से अधिकारियों ने दिया है।
राशनकार्ड धारियों के लिए प्रति यूनिट 5 किलोग्राम राशन देना अनिवार्य बनाया गया है। लेकिन डीलर ऐसा नही करते हैं। 5 किलो अनाज की जगह पूरे धौंस के साथ 4 किलोग्राम अनाज ही देते हैं। एक किलोग्राम अनाज का यह अंतर छोटा नही होता। हर डीलर के कार्यक्षेत्र में सैकड़ों राशनकार्ड धारी होते हैं और इस तरह सैंकड़ों किलोग्राम अनाज की कालाबाजारी हर महीने नियमित रूप से होती रहती है। इस भ्रष्टाचार में डीलर से लेकर अधिकारी तक शामिल होते हैं जिससे इस भ्रष्टाचार को संरक्षण मिलता है। प्रश्न यह है कि राशनकार्ड धारी के लगातार हो रहे इस शोषण को कौन रोकेगा ? सरकार कोई प्रभावी कदम इसलिए नही उठा पाती है क्योंकि इससे वोटबैंक प्रभावित नही होता है और कार्ड धारियों में न इतनी जागरूकता होती है और न डीलर-अधिकारियों के गठजोड़ से लड़ने का साहस होता है। नतीजा यह है कि हर महीने सैंकड़ों किलोग्राम अनाज की कालाबाजारी बेधड़क जारी है और इसे राज्य स्तर पर देखा जाए तो सैंकड़ों टन अनाज की कालाबाजारी का मामला बनता है गरीबों के नाम पर और दावा किया जाता है कि गरीबी दूर करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू में आरम्भिका के चौथे दिन स्वास्थ्य, नवाचार और सामाजिक सेवा का संदेश

मेट्रोरेज संवाददाता

मेदिनीनगर : गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, पलामू में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आयोजित इंडक्शन प्रोग्राम ह्यआरम्भिका 2026ह्व के चौथे दिन स्वास्थ्य, नवाचार, रचनात्मकता एवं सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक सत्र आयोजित किए गए।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजीव शरण, झारखंड ग्रामीण बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी तथा पतंजलि परिवार, पलामू के जिला प्रभारी सह झारखंड राज्य कार्यकारिणी सदस्य रहे। वर्ष 2006 से पतंजलि संस्थान से जुड़े श्री शरण योग शिक्षक एवं प्रशिक्षक के रूप में जिले में सेवा कार्य कर रहे हैं।
विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए श्री राजीव शरण ने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यभार के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए पढ़ाई के साथ शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है। उन्होंने

विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए विभिन्न योगासनों एवं उनके लाभों की जानकारी दी तथा नियमित योग और अनुशासित दिनचर्या को बेहतर स्वास्थ्य एवं एकाग्रता का आधार बताया।
इसके बाद संस्थागत नवाचार परिषद (क्क्र 8.0) के अंतर्गत विद्यार्थियों को नवाचार, उद्यमिता, स्टार्टअप, डिजाइन थिंकिंग, समस्या समाधान, बौद्धिक संपदा अधिकार (क्ढफ) एवं पेटेंट की जानकारी दी गई। साथ ही युक्ति-कपिला योजना एवं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन (स्क्ल) के बारे में भी बताया गया। आईआईसी के अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर ने विद्यार्थियों को अपने नए विचारों पर कार्य करने तथा समाज की समस्याओं के अभिनव समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया।
कार्यक्रम में साहित्यिक क्लब ने विद्यार्थियों को लेखन के माध्यम से अपने विचारों एवं भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। वहीं उड़ान भारत ने जरूरतमंद एवं आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की सहायता के लिए किए जा रहे सामाजिक कार्यों की जानकारी साझा की।
आरम्भिका का चौथा दिन विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य, नवाचार, रचनात्मकता एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़ी महत्वपूर्ण सीख लेकर आया। कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि एक सफल इंजीनियर बनने के लिए तकनीकी ज्ञान के साथ स्वस्थ जीवनशैली, नवाचार की सोच, रचनात्मक अभिव्यक्ति एवं समाज के प्रति जिम्मेदारी भी आवश्यक है।
कार्यक्रम के सफल आयोजन में इंडक्शन प्रोग्राम के संयोजक डॉ. सुमित कुमार एवं समन्वयक डॉ. मुरली मनोहर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

आभूषण कारोबारियों की सुरक्षा को लेकर डीजीपी व एडीजी कानून-व्यवस्था से होगा सीधा संवाद

संवाददाता

पटना : बिहार में लगातार आभूषण कारोबारियों एवं स्वर्ण व्यवसायियों के साथ हो रही लूट, हत्या और अन्य आपराधिक घटनाओं को लेकर कैट/एआईजेजीएफ बिहार की ओर से आभूषण कारोबारियों की सुरक्षा के विषय पर विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
यह कार्यक्रम 15 सितंबर, मंगलवार को शाम 4 बजे पटना के पटेल भवन, बेली रोड में आयोजित होगा। कार्यक्रम में बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, भारतीय पुलिस सेवा तथा अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) के. एस. अनुपम, भारतीय पुलिस सेवा आभूषण कारोबारियों से सीधे संवाद करेंगे। इस दौरान कारोबारियों की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों, समस्याओं और आवश्यक उपायों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
कार्यक्रम में विशेष रूप से पिछले 15 दिनों के दौरान आपराधिक घटनाओं के शिकार हुए आभूषण कारोबारियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा जिन कारोबारियों के साथ पूर्व में लूट, चोरी, हत्या अथवा अन्य आपराधिक घटनाएं हुई हैं, वे भी अपनी प्राथमिकी की प्रति साथ लेकर कार्यक्रम में उपस्थित हो सकते हैं। उन्हें अपनी समस्या और सुझाव सीधे पुलिस अधिकारियों के समक्ष रखने का अवसर मिलेगा।
कैट/एआईजेजीएफ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा एवं प्रदेश उपाध्यक्ष बबल कश्यप ने कहा कि बिहार के आभूषण कारोबारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस प्रशासन और व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा आभूषण कारोबारियों की सुरक्षा के लिए ठोस और प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
उन्होंने कहा कि लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए कारोबारियों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता है। संवाद के माध्यम से व्यापारियों की जमीनी समस्याओं को समझकर उनके समाधान और सुरक्षा के प्रभावी उपायों पर ठोस पहल की उम्मीद है।

जन्मदिन पर इंदर सिंह नामधारी को हृदयानंद मिश्र ने दी हार्दिक बधाई

कहा- राजनीतिक शुचिता, सिद्धांत और संसदीय गरिमा की प्रेरणादायी मिसाल हैं नामधारी

मेट्रोरेज संवाददाता

मेदिनीनगर : झारखंड प्रदेश राजीव गांधी विचार समिति के अध्यक्ष एवं अधिवक्ता हृदयानंद मिश्र ने झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, वरिष्ठ राजनेता एवं समाजसेवी आदरणीय इंदर सिंह नामधारी जी को जन्मदिन एवं वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएँ दी हैं।
श्री मिश्र ने कहा कि इंदर सिंह नामधारी जी का सार्वजनिक जीवन ईमानदारी, राजनीतिक शुचिता, सादगी, सिद्धांतनिष्ठा और जनसेवा की प्रेरणादायी मिसाल रहा है। झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय मर्यादाओं और स्वस्थ राजनीतिक परंपराओं को जिस गरिमा के साथ प्रतिष्ठित किया, वह आज भी सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
उन्होंने कहा कि राजनीति में पद महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन पद पर रहते हुए स्थापित किए गए आदर्श उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। नामधारी जी ने अपने दीर्घ सार्वजनिक जीवन में सिद्धांतों से समझौता न करते हुए यह प्रमाणित किया है कि राजनीति में रहते हुए भी सादगी, स्पष्टवादिता, नैतिकता और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा सकती है।
हृदयानंद मिश्र ने कहा कि जन्मदिन और वैवाहिक वर्षगांठ का यह सुखद संयोग उनके जीवन में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य, पारिवारिक आनंद और दीघार्यु लेकर आए। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि नामधारी जी सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें और उनका स्नेह, मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद समाज तथा सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को निरंतर मिलता रहे।
उन्होंने कहा कि इंदर सिंह नामधारी जी जैसे वरिष्ठ सार्वजनिक व्यक्तित्व किसी एक राजनीतिक दल या पीढ़ी की धरोहर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक और सार्वजनिक जीवन की साझा विरासत होते हैं। उनकी दीर्घ सार्वजनिक यात्रा और उनके स्थापित राजनीतिक आदर्श नई पीढ़ी के लिए सदैव प्रेरणा देते रहेंगे।
श्री मिश्र ने पुनः आदरणीय इंदर सिंह नामधारी जी को जन्मदिन-वर्षगांठ की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएँ देते हुए उनके स्वस्थ, सुखी, सम्मानपूर्ण एवं दीर्घ जीवन की मंगलकामना की।

बैंकों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह के प्रस्ताव के पक्ष में नहीं कैट : एआईजीएफ बिहार

संवाददाता

पटना : बैंक कर्मचारियों की ओर से बैंकों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की मांग के बीच कैट एवं एआईजेजीएफ बिहार ने इस प्रस्ताव पर असहमति जताई है। संगठनों का कहना है कि बैंकिंग व्यवस्था सीधे तौर पर व्यापार, उद्योग और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। ऐसे में बैंकों के कार्यदिवस कम करने का निर्णय केवल कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखकर नहीं लिया जाना चाहिए।
कैट एवं एआईजेजीएफ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में बैंक कर्मचारियों को महीने में लगभग छह दिनों का अवकाश मिलता है। ऐसे में बैंकों को वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही संचालित किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि व्यापारियों तथा छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए बैंकिंग सेवाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। यदि बैंक सप्ताह में केवल पांच दिन ही खुलेंगे, तो इसका सीधा असर नकद जमा, भुगतान, चेक निपटान, त्वरित सकल निपटान प्रणाली और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण जैसी सेवाओं पर पड़ सकता है। इससे व्यापारिक गतिविधियों में अनावश्यक बाधा उत्पन्न होने की आशंका है।
अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि बैंकिंग सेवाओं में किसी भी प्रकार का बदलाव करने से पहले सरकार को व्यापारियों, उद्योग जगत और अन्य बैंकिंग उपभोक्ताओं के हितों पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कैट एवं एआईजेजीएफ बैंक कर्मचारियों के हितों का सम्मान करते हैं, लेकिन बैंकिंग व्यवस्था पूरे व्यापार और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए वर्तमान कार्य व्यवस्था को बनाए रखना व्यापार एवं आर्थिक गतिविधियों के व्यापक हित में अधिक उचित होगा।
संगठनों ने सरकार से आग्रह किया कि पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने से पहले इसके व्यापार और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का व्यापक आकलन किया जाए।

मैट्रिक-इंटर के 168 मेधावी विद्यार्थी सम्मानित

अगले साल से परिणाम के एक माह में होगा टॉपर सम्मान समारोह

पटना : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को लोक सेवक आवास स्थित ह्यनेक संवादह्व सभागार में इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक वार्षिक परीक्षा-2026 की टॉपर सूची में स्थान प्राप्त करने वाले 168 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को पदक, प्रशस्ति पत्र एवं सांकेतिक चेक प्रदान किए गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सम्मानित विद्यार्थी बिहार के उज्ज्वल भविष्य की पहचान हैं। उनकी सफलता उनके परिश्रम, प्रतिभा और लगन का परिणाम है। उन्होंने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि वे अपनी प्रतिभा और ज्ञान का उपयोग बिहार को विकसित एवं समृद्ध बनाने में करें।
प्रथम स्थान पाने वालों को दो लाख रुपये
इंटरमीडिएट और मैट्रिक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को दो लाख रुपये, द्वितीय स्थान पाने वालों को डेढ़ लाख रुपये तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को एक लाख रुपये की राशि दी गई। इंटरमीडिएट में चौथे एवं पांचवें स्थान पर रहे विद्यार्थियों को 30 हजार रुपये तथा मैट्रिक में चौथे से दसवें स्थान तक के विद्यार्थियों को 20 हजार रुपये प्रदान किए गए। सभी सम्मानित विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए अतिरिक्त 51 हजार रुपये भी दिए गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक टॉपर विद्यार्थियों का सम्मान नवंबर-दिसंबर में किया जाता था। अधिकारियों से समीक्षा के बाद उन्होंने निर्देश दिया है कि अगले वर्ष से परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक महीने के भीतर टॉपर सम्मान समारोह आयोजित किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धि के लिए समय पर सम्मान और प्रोत्साहन मिल सके।
700 विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने बिहार के गौरवशाली शैक्षणिक इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने बिहार को प्राचीन काल से ही ज्ञान और शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाया। उन्होंने कहा कि राज्य के गौरवशाली शैक्षणिक अतीत को आधुनिक सुविधाओं के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि 700 सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कोचिंग, सीधी कक्षा और सीधे शिक्षक से पढ़ाई जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। पूर्ववर्ती विद्यार्थियों से भी अपने विद्यालय और वहां पढ़ने वाले बच्चों के लिए योगदान देने का आह्वान किया गया।
युवा नौकरी लेने वाले नहीं, देने वाले बनें
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प विकसित भारत और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संकल्प ह्यसमृद्ध बिहार है। इसे पूरा करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
उन्होंने कहा कि बिहार तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और इस विकास यात्रा में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। युवा केवल नौकरी पाने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें। राज्य में अब तक एक हजार उद्योगों के लिए भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है। औद्योगिक विकास के साथ युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं।
बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान पर जोर
राज्य में बाढ़ की स्थिति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 38 प्रतिशत कम वर्षा के बावजूद बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य को लगभग हर वर्ष बाढ़ की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसलिए केवल राहत और बचाव कार्य तक सीमित रहने के बजाय इसके स्थायी समाधान की दिशा में काम करना जरूरी है।
उन्होंने जल-चक्र और प्राकृतिक जल-प्रवाह तंत्र को बेहतर एवं व्यवस्थित करने के लिए दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करने की बात कही, ताकि बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान तलाशा जा सके।
सहयोग पोर्टल से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान
मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को आवश्यक सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए ह्यसहयोग पोर्टलह्व संचालित किया जा रहा है। इसमें विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के साथ उनके सुझाव देने की भी व्यवस्था है। उन्होंने विद्यार्थियों से विकसित और समृद्ध बिहार के निर्माण के लिए अपने सुझाव देने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने सम्मानित विद्यार्थियों से कहा कि वे दूसरे विद्यार्थियों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा मिलने से जीवन प्रकाशमय हो जाता है। विद्यार्थी अपनी प्रतिभा और ज्ञान का उपयोग बिहार के विकास में करें तथा अपनी जन्मभूमि को बेहतर बनाने में योगदान दें।